धनबाद, गुरूवार
6 अगस्त 2026
वर्ष : 03 अंक : 307
पृष्ठ : 08
मूल्य: 3 /-
E-Mail:-truthpath941@gmail.com

हिन्दी दैनिक समाचार

ट्रूथ पथ

ब्रीफ न्यूज

2047 तक भारत में होंगे 3 हजार से ज्यादा विमान, 350 से अधिक एयरपोर्ट का लक्ष्य

नई दिल्ली (एजेंसी) : भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक बड़े विस्तार का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विमानन क्षेत्र का विजन साझा करते हुए कहा कि 2047 तक देश में 3 हजार से ज्यादा विमानों का बेड़ा और 350 से अधिक हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, आने वाले पांच वर्षों में भारतीय विमान बेड़े में 500 नए विमान शामिल किए जाएंगे। फिलहाल देश में करीब 860 विमान हैं, जबकि 1,640 नए विमानों की डिलीवरी भी आने वाले समय में होनी है। सरकार का जोर देश में विमानन से जुड़े प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करने पर भी है।राम मोहन नायडू ने बताया कि भारत में प्रशिक्षण, भारत में उड़ान पहल के तहत पायलटों और विमानन क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मचारियों को देश में ही प्रशिक्षण देने की दिशा में काम किया जा रहा है। नए उड़ान प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। शुरूआत में प्रत्येक केंद्र में 60 से 70 प्रशिक्षण विमान होंगे, जिन्हें बाद में 110 से 120 तक बढ़ाया जा सकेगा।

सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने कई कदमों की जानकारी दी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय फिलहाल उन हवाई पट्टियों का आकलन कर रहा है जहां निगरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान होने वाले हादसों की जिम्मेदारी उड़ान प्रशिक्षण संगठनों की होगी और सरकार उन्हें आवश्यक सहयोग देगी।

यूपी-झारखंड में बारिश-बिजली गिरने से 17 मौतें

नई दिल्ली(एजेंसी) : देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। झारखंड में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा 9 मौतें गिरिडीह, 3 दुमका और 2 लातेहार जिले में हुईं। यूपी के मिर्जापुर में 3 लोगों की जान चली गई। दो बच्चों की मौत गड्ढे में डूबने से हुई। एक 25 साल के युवक पर बिजली गिर गई। दूसरी ओर केरलम में 1 अगस्त से लगातार बारिश ने अब तक 25 लोगों की जान ले ली है, जबकि 4 लोग लापता हैं। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण हजारों लोगों को घर छोड़ने पड़े हैं।

केरलम सरकार के मुताबिक, 18 हजार से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित पथनमथिट्टा, कोट्टायम और अलप्पुझा जिले हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 300 से ज्यादा सडकें बंद हैं। इनमें हिमाचल की 160 और उत्तराखंड की 100 से ज्यादा सडकें शामिल हैं। उत्तराखंड के देहरादून और बागेश्वर में 12वीं तक के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है।

राज्यसभा सभापति की चेतावनी, वेल में आने और प्लेकार्ड दिखाने पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली,(एजेंसी) : संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध के बीच राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने सदस्यों को स्पष्ट चेतावनी दी कि सदन के वेल में आने और प्लेकार्ड दिखाने जैसी गतिविधियां नियमों के विरुद्ध हैं तथा ऐसा करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही पुनः शुरू होने पर सभापति ने सभी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे अपनी-अपनी सीटों पर रहें और सदन की गरिमा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि यदि कोई सदस्य इन निदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसे बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए वे बाध्य होंगे।

सभापति की अपील के बावजूद विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जारी रही।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर 22 हस्तियों को मिलेंगे प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार

नई दिल्ली,(एजेंसी) : राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर 7 अगस्त को आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू भारत के हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 22 पुरस्कार विजेताओं को प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार-2025 प्रदान करेंगी। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर तथा देशभर से आए अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे।वस्त्र मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष कुल 22 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार तथा 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। इन सम्मानों के माध्यम से भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा के संरक्षण, संवर्धन, नवाचार और वैश्विक पहचान बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान देने वाले बुनकरों, डिजाइनरों, संस्थानों और अन्य हितधारकों को सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा

विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत संचालित हथकरघा विपणन सहायता (एचएमए) घटक के तहत दिए जाते हैं और इन्हें हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। पुरस्कारों का उद्देश्य उत्कृष्ट शिल्प कौशल, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, आधुनिक तकनीकों को अपनाने, विपणन पहल, स्टार्ट-अप उद्यमों तथा उत्पादक कंपनियों को प्रोत्साहित करना है।

संत कबीर हथकरघा पुरस्कार हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। यह उन कारीगरों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने आजीवन समर्पण के साथ भारत की पारंपरिक बुनाई कला को संरक्षित और समृद्ध किया है। इस पुरस्कार में सोने का सिक्का, ताम्रपत्र, शॉल और प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

वहीं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उत्कृष्ट रचनात्मकता, गुणवत्ता, नवाचार और शिल्प कौशल के लिए दिया जाता है। इस सम्मान में ताम्रपत्र, शॉल और प्रमाण-पत्र शामिल हैं। इसका उद्देश्य कारीगरों और संस्थानों को भारतीय हथकरघा परंपराओं को संरक्षित रखते हुए उत्पाद विकास और बाजार विस्तार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है।

वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार विजेताओं का चयन पारदर्शी और बहु-स्तरीय प्रक्रिया के तहत किया जाता है। बुनाई श्रेणी के लिए जोनल, मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियां नामांकनों का मूल्यांकन करती हैं, जबकि डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्ट-अप और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों का चयन भी विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। मंत्रालय का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में वास्तविक उत्कृष्टता को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्मानित करना है।

जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती विवाद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से की मुलाकात

रांची, (एजेंसी) : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की नियुक्ति प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं तथा इसके विरोध में रांची में चल रहे छात्र आंदोलन की जानकारी राज्यपाल को दी।

बैठक के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भर्ती एवं परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं का विश्वास हर हाल में कायम रहना चाहिए। राज्यपाल ने कथित अनियमितताओं को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि आयोगों की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिससे उनकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का प्रश्नचिह्न न लगे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी उपस्थित

झारखंड में प्रारूप मतदाता सूची जारी, 5 सितंबर तक नाम जोड़ने और सुधार का मिलेगा मौका

रांची । झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) और एएसडीडी सूची का प्रकाशन कर दिया गया. यह सूची राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आम नागरिकों के लिए उपलब्ध करा दी गई है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थायी और महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसलिए प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक को इसमें अपना नाम अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत तैयार की जा रही मतदाता सूची भविष्य में भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज के रूप में उपयोग की जाएगी.

उन्होंने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, मतदाता सूची में नाम, पता, उम्र या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से सुधार भी कराया जा सकता है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में अब तक 2 करोड़ 21 लाख 1 हजार 249 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त और डिजिटाइज किए जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 83.51 प्रतिशत है. जबकि विभिन्न कारणों से करीब 43.61 लाख गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सके.

उन्होंने कहा कि मतदाता मोबाइल एप, और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड की वेबसाइट के माध्यम से अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं. वेबसाइट पर और लिंक उपलब्ध कराए गए हैं.

जिला, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र का चयन कर मतदाता संबंधित पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. सूची में प्रत्येक नाम के साथ सूची में शामिल किए जाने का कारण भी अंकित है.

ऑफलाइन व्यवस्था के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रारूप मतदाता सूची और अर सूची की मुद्रित प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत कार्यालयों और शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी इनका प्रदर्शन किया जाएगा. इसके अलावा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट , जिला निर्वाचन पदाधिकारी , निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी कार्यालयों में भी सूची उपलब्ध रहेगी.

के. रवि कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे स्वयं अपना नाम और विवरण जांचें और अपने परिवार, पड़ोस, मित्रों और अन्य पात्र नागरिकों को भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं त्रुटियों के सुधार के लिए प्रेरित करें. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए.

उन्होंने कहा आपत्ति की प्रक्रिया 5 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगी. इसके बाद 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक नोटिस, सुनवाई और सत्यापन की कार्रवाई होगी. अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना नोटिस जारी किए और कारणयुक्त आदेश पारित किए किसी भी मतदाता का नाम प्रारूप मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा.

झारखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के लिए आज सर्वदलीय बैठक

रांची(एजेंसी) : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू होगा। ये सत्र 6 दिन चलेगा। सत्र से पहले बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सत्र के सुचारू संचालन को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के दौरान रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन का मुद्दा प्रमुखता से उठा। विभिन्न दलों के नेताओं ने सरकार से आंदोलनरत छात्रों से शीघ्र बातचीत कर समाधान निकालने की पहल करने की मांग की।

माना जा रहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा मानसून सत्र में प्रमुखता से गूंजेगा। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, जेएलकेएम विधायक जयराम महतो, आजसू विधायक निर्मल महतो, लोजपा विधायक सुरेश पासवान और अन्य दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

आंदोलनरत छात्रों से बातचीत करे सरकारः जयराम महतो

बैठक में सदन की कार्यवाही लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मयार्दाओं के अनुरूप संचालित करने पर सहमति बनी। जेएलकेएम विधायक

जयराम महतो ने बैठक में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्रों के आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सरकार बिना विलंब आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करे।

उन्होंने नियुक्ति घोटाले पर सदन में कम से कम दो घंटे की विशेष चर्चा कराने और राज्य में सूखे की स्थिति पर भी विस्तृत बहस की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद कहा कि विधानसभा जनता की आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वोच्च मंच है। सरकार जनहित के हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा, जवाबदेही और सकारात्मक संवाद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी राजनीतिक दल झारखंड के हित को सर्वोपरि रखते हुए सदन की कार्यवाही को सफल बनाएंगे।

बैठक में 14वीं-16वीं खढरउ परीक्षा को रद्द करने की छात्रों की मांग पर चर्चा

बैठक में शामिल हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आगामी मानसून सत्र में जनता के सवालों को प्रभावी ढंग से उठाने की रणनीति तैयार की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में 14वीं और 16वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की छात्रों की मांग पर चर्चा हुई। जेपीएससी परीक्षा से जुड़े विवादों और चल रही जांच की प्रगति की समीक्षा करने की बात कही गई।

प्रदीप यादव ने कहा कि इसके बाद होने वाली महागठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष छात्रों के इन तमाम मुद्दों को प्रमुखता से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों का हित हमारी पहली प्राथमिकता है। सरकार ऐसा रास्ता निकालेगी, जिससे राज्य की साख भी बची रहे और छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित रहे।

6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में कुल पांच कार्य दिवस होंगे। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा।

अनुच्छेद 370 हटने के सात साल, जमीनी बदलाव को सामने रखने की कोशिश

नई दिल्ली (एजेंसी) : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के करीब सात साल पूरे होने के बीच केंद्र सरकार की नीतियों और क्षेत्र में हुए बदलावों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज है। इस दौरान जम्मू-कश्मीर में विकास, सुरक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुए बदलावों को सरकार की बड़ी

उपलब्धियों के तौर पर पेश किया जा रहा है। वहीं, इन बदलावों का आम लोगों की जिंदगी पर कितना असर पड़ा, इसे जमीनी स्तर पर परखने की जरूरत भी बताई जा रही है।

पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में विभाजित किया गया। इस फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे और राजनीतिक गतिविधियों में बड़े बदलाव देखने को मिले।समर्थकों का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिला, निवेश की संभावनाएं बढ़ीं और सड़क, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास में तेजी आई। आतंकवाद से प्रभावित इलाकों में भी सुरक्षा स्थिति में सुधार का दावा किया गया है।

जम्मू-कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र को विशेष रूप से बदलाव का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और अन्य पर्यटन स्थलों पर बढ़ती गतिविधियों को आर्थिक बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रोजगार, सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जैसे मुद्दे अब भी बहस के केंद्र में हैं। ऐसे में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल बाद जम्मू-कश्मीर की वास्तविक तस्वीर को केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि आम लोगों के अनुभवों और जमीनी परिस्थितियों से समझना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आदिवासी महोत्सव की तैयारियों को लेकर अपर मुख्य सचिव ने मोराबादी मैदान का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

तैयारियां समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएंः वंदना दादेल

रांची(एजेंसी) : गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना दादेल ने मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले आदिवासी महोत्सव 2026 की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आयोजन स्थल पर चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि सभी तैयारियां समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं।

श्रीमती दादेल ने सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं आगंतुकों की सुविधा से जुड़े सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि महोत्सव में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा आयोजन राज्य की सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप भव्य और सुव्यवस्थित हो।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंच निर्माण, स्टॉल व्यवस्था, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी एजेंसियां मिलकर कार्य करें ताकि आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इस अवसर पर कल्याण आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी, विशेष सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री राजीव लोचन बक्शी, उपायुक्त रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री, ळफक्र निदेशक श्री आलोक एस कच्छप, नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा सहित कई विभाग के पदाधिकारी

संक्षिप्त खबरें

सयकेला-खरसावां में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित,7 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम सूची

सारायकेला (एजेंसी) : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे एस-आईआर-2026 के तहत सरायकेला-खरसावां जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) ने प्रारूप-5 के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों एवं अधिसूचित स्थलों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कराया है। अब मतदाता अपने नाम एवं विवरण का सत्यापन कर सकेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन एवं अन्य सुधार के लिए दावा एवं आपत्ति स्वीकार किए जाएंगे। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन 3 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को होगा।जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने सभी पात्र मतदाताओं से अपने-अपने मतदान केंद्र पर प्रदर्शित प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन करने की अपील की है।उन्होंने कहा कि यदि नाम, पता अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) के समक्ष दावा या आपत्ति प्रस्तुत करें। साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिक प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कल्याण विभाग की ओर से 69 विद्यार्थियों को दी गई साइकिल

खूंटी (एजेंसी) : कल्याण विभाग खूंटी की ओर से कर्रा प्रखंड के तीन विद्यालयों में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। साइकिल वितरण का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च विद्यालय तक पहुंचने में सुविधा देना है और ड्रॉप आउट की समस्या को कम करना है। कर्रा प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय घुनसूली के 26, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पदमपुर के 24 और राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहागड़ा के 19 विद्यार्थियों को साइकिल दी गई। इस दौरान प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनमोहन साहू सहित तीन विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक मौजूद थे। बताया गया कि कई गांव से उच्च विद्यालय की दूरी करीब 10 किलोमीटर तक है दूरी अधिक होने के कारण कई विद्यार्थी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते थे। साइकिल मिलने से अब विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा होगी और समय की भी बचत होगी। साइकिल पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। विद्यार्थियों ने कहा कि अब उन्हें पैदल लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। समय पर विद्यालय पहुंचने में मदद मिलेगी।

जिरवाबाड़ी में विवाहिता की मौत, दहेज ,हत्या का केस दर्ज, पति गिरफ्तार

साहिबगंज (एजेंसी) : जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के बड़ा पंचगढ़ गांव में 25 वर्षीय विवाहिता निशा कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतका के पिता संजय कुमार मिश्रा के बयान पर जिरवाबाड़ी थाना में कांड संख्या 141/26 दर्ज किया गया है। मामले में आरोपी पति सुमित पाठक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद से ही निशा कुमारी को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि दहेज नहीं मिलने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया जाता था तथा इसी कारण उसकी हत्या कर दी गई।दर्ज प्राथमिकी में पति सुमित पाठक के अलावा उसके भाई, बहन, सास और जीजा को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है।गौरतलब है कि घटना के बाद ससुराल पक्ष ने पुलिस को बताया था कि निशा कुमारी बाथरूम से निकलते समय फिसल गई थी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था।जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी शशि सिंह ने बताया कि मृतका के पिता के आवेदन पर कांड संख्या 141/26 दर्ज कर ली गई है। आरोपी पति सुमित पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नामजद अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच में जुटी है।

खास महाल के लीजधारी नवीनीकरण के लिए 15 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

हजारीबाग (एजेंसी) : हजारीबाग के खास महाल प्रकोष्ठ द्वारा जिले के सभी खास महाल ने लीज धारियों व उनके वैध उत्तराधिकारी नवीनीकरण के लिए 15 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद नवीनीकरण नहीं कराने वालों की लीज समाप्त न कर दी जाएगी।जिला प्रशासन ने जारी की सूचना के अनुसार, हजारीबाग खास महाल क्षेत्र की न लीज भूमि का प्रत्येक 30 वर्ष के लिए लीज नवीकरण किया जाता है।अधिकांश लीज धारियों की लीज अवधि 31 मार्च 2008 को समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद कई लीज धारियों अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों द्वारा अगले 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण, नामांतरण, उत्तराधिकारी नामांतरण, हस्तांतरण, प्रयोजन परिवर्तन, बंदोबस्ती एवं वंशावली संबंधी आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ अब तक जमा नहीं किए गए हैं, जिसके कारण लीज नवीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है।खास महाल प्रकोष्ठ ने ऐसे सभी लीज धारियों वं उनके वैध उत्तराधिकारियों से अपील की है कि जिनका उपर्युक्त कार्य अब तक लंबित है, वे 15 अगस्त 2026 तक आवेदन-पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित खास महाल प्रकोष्ठ, हजारीबाग में जमा कर सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर लीज नवीकरण एवं अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को पूर्ण कराने में सहयोग करें, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन हो सके।जिनकी लीज समाप्त हो गई है नवीनीकरण भी नहीं करा रहे हैं

पंचायत सहायकों ने मुख्यमंत्री को सौंपा 8 सूत्री मांग पत्र, मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगें उठाईं

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : झारखंड प्रदेश पंचायत सहायक संघ ने पंचायत सहायकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान और आठ सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में पंचायत सहायकों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया गया है।ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को सुदृढ़, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रही है। पंचायत सहायक सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभुकों का डाटाबेस तैयार करने, जागरूकता अभियान, सामाजिक सहभागिता एवं मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं। इसके बावजूद पंचायत सहायकों को अपेक्षित सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

संघ ने कहा कि वर्तमान में मिलने वाली ₹2500 की प्रोत्साहन राशि से परिवार का भरण-पोषण करना महंगाई के दौर में अत्यंत कठिन हो गया है। आर्थिक तंगी के कारण पंचायत सहायकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।संघ ने मुख्यमंत्री से 8 सूत्री मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। प्रमुख मांगों में मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता, सम्मानजनक मानदेय लागू करना, प्रत्येक वर्ष ग्रामसभा अनुमोदन की अनिवार्यता समाप्त करना, पंचायत सचिव भर्ती में 70 प्रतिशत आरक्षण, मृत पंचायत सहायकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, नगर निगम एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में समायोजन, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा का लाभ तथा पंचायत सहायकों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल का गठन शामिल है।संघ के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार ने मुख्यमंत्री से पंचायत सहायकों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर मांगों को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पंचायत सहायकों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेती है तो राज्यभर के पंचायत सहायकों में उत्साह का संचार होगा और वे ग्राम विकास के कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे।

होटल से एक किलो गांजा समेत 147 बोतल अवैध शराब बरामद,एक गिरफ्तार

बोकारो (एजेंसी) : बोकारो जिला के महुआटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत फुटकाडीह गांव में पुलिस ने बुधवार को अवैध शराब और मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राहुल कुमार गुप्ता उर्फ कुंदन कुमार गुप्ता पिता बुटन साव के होटल में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने एक किलो गांजा के अलावा विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी अवैध शराब व बीयर की कुल 147 बोतलें बरामद की।साथ ही, बुटन साव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फुटकाडीह निवासी राहुल कुमार गुप्ता उर्फ कुंदन कुमार गुप्ता के होटल में अवैध रूप से शराब और मादक पदार्थ की बिक्री की जा रही है।सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ बेरमो रवींद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गयी। टीम ने होटल में छापेमारी कर तलाशी ली, जहां से गांजा और भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। बरामद शराब में रॉयल चैलेंज की 375 एमएल की चार, 180 एमएल की 10 और 750 एमएल की तीन बोतलें, स्टर्लिंग रिजर्व बी-7 की 180 एमएल की 25 और 375 एमएल की छह बोतलें, आइकॉनिक व्हाइट की 180 एमएल की 12 और 375 एमएल की सात बोतलें, मैकडॉवेल नंबर-1 की 180 एमएल की 14 और 375 एमएल की 10 बोतलें, 8 पीएम प्रीमियम ब्लैक की 375 एमएल की 5 बोतलें तथा रॉयल स्टैग की 300 एमएल की 13 प्लास्टिक बोतलें शामिल हैं।इसके अलावा किंगफिशर बीयर की 650 एमएल की 38 बोतलें भी बरामद की गयीं। पुलिस ने बरामद एक किलो गांजा और 147 बोतल शराब/बीयर को जब्त कर लिया है।

30 दिवसीय मोटर व्हीकल ट्रेनिंग का उद्धाटन

खूंटी (एजेंसी) : ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर. सेटी.) में 30 दिवसीय लाइट मोटर व्हीकल ट्रेनिंग का उद्घाटन किया गया। लाइट मोटर व्हीकल ट्रेनिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को कुशल ड्राइविंग सिखाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। खूंटी जिला परिषद के अध्यक्ष मसीह गुड़िया ने दीप प्रज्वलित कर ट्रेनिंग का उद्घाटन किया। आरसेटी में कुल 35 प्रशिक्षुओं ने ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए निःशुल्क पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मसीह गुड़िया ने कहा कि सड़क सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सही ट्रेनिंग और यातायात नियमों की जानकारी ही सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकती है। आर सेटी संस्थान खूंटी जिला के युवक युवतियों को निशुल्क आवासीय ड्राइविंग प्रशिक्षण देने के क्रम में इस दिशा में एक बेहतरीन पहल की है। कार्यक्रम में आरसेटी खूंटी के निदेशक बसंत कुमार हजाम एवं वरिष्ठ संकाय सदस्य सुशील कुमार उपस्थित थे। उन्होंने यह जानकारी दी कि आर सेटी खूंटी प्रत्येक वर्ष खूंटी जिला के युवक युवतियों के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार संबंधित ट्रेनिंग आयोजित करता है। आर सेटी में निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है इसके साथ ही उन्होंने अगस्त में शुरू होने वाले 30 दिवसीय प्लंबिंग फिटिंग प्रशिक्षण के शुरू होने की जानकारी दी जिसका पंजीकरण केंद्र कार्यालय में प्रारंभ किया जा चुका है।

एसआइटी गठित कर परीक्षा में धांधली की जांच कराये सरकार : इंडिया गठबंधन

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (भाकपा) राज्य कार्यालय सभागार में परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की एक बैठक बुलाई गयी। इस सर्वदलीय बैठक में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ चल रहे आंदोलन और छात्रों की मांगों को लेकर व्यापक रूप से विमर्श करते हुए कई निर्णय लिये गये।बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश महासचिव इरफान अहमद अंसारी ने की। इसमें कांग्रेस, भाकपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस, माले लोक सेवा समिति, मुस्लिम मजलिसे उलेमा, आइसा, एआइएसएफ, एआइवाइएफ, एसफआइ शामिल हुए।बैठक में राज्य के छात्रों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रतियोगी परीक्षाओं की अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (एस-आइटी) का गठन, परीक्षा का संचालन किसी विश्वसनीय घरेलू एजेंसी से कराने, छात्रों को स्कॉलरशिप का समय पर भुगतान समय पर सुनिश्चित करने, छात्रों के साथ वार्ता कर आंदोलन समाप्त कराने को लेकर झारखंड सरकार से विशेष हस्तक्षेप की मांग की गयी।बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 6 अगस्त की सुबह 9 बजे इंडिया गठबंधन के साथ ही विभिन्न छात्र संगठनों का प्रतिनिधिमंडल श्रम एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में गठबंधन से जुड़े विभिन्न दलों के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।बैठक में राजद के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र महतो, कांग्रेस से योगेंद्र सिंह, भाकपा माले से आर एन सिंह, भाकपा से अजय कुमार, कृष्णा कुमार वर्मा, एआइएमएमयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल्लाह अजहर सहित विभिन्न राजनीतिक दलों एवं छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।छात्र संगठनों की ओर से ओजस्वी राज, अमन, दानिश, त्रिलोकी नाथ, हिमांशु सिंह, अफजल दुर्रानी, एहतेशाम परवीन, तेजू मिर्धा सहित अन्य छात्र संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

टंडवा घटना पर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने किया दौरा, शांति और निष्पक्ष जांच की मांग

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने मंगलवार को चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़गांव, मगहिया टोला का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और घटनास्थल का जायजा लिया। उनके साथ महानगर अध्यक्ष हुसैन खान, महासचिव अरशदुल कादरी तथा तौकीर अख्तर भी उपस्थित रहे।दौरे के क्रम में मंजूर अंसारी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय लोगों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना तथा प्रशासन एवं संबंधित डीएसपी से बातचीत कर जनता की उचित मांगों के समाधान का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से शांति एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की।गौरतलब है कि सोमवार शाम एक नाबालिग लड़की के लापता होने के बाद मंगलवार को उसके वापस लौटने पर उसने 25 वर्षीय मोहम्मद इमरोज पर अपहरण एवं दुष्कर्म का आरोप लगाया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल इमरोज की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।इस घटना पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने स्पष्ट कहा कि कानून को हाथ में लेना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है और दोषी को न्यायालय के माध्यम से ही दंड मिलना चाहिए।प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने मांग की कि पीड़िता को शीघ्र न्याय एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।साथ ही प्रशासन से क्षेत्र में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई। प्रदेश कांग्रेस ने पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए निष्पक्ष जांच जारी रखने की उम्मीद जताई।

एबीवीपी ने जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती में अनियमितता पर निकाला मार्च

रांची (एजेंसी) : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र मार्च निकाला। डीएसपीएमयू परिसर से मार्च अलबर्ट एक्का चौक पहुंचा। यहां पर पुतला दहन करते हुए प्रदर्शन किया गया। मार्च के दौरान विद्यार्थियों ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग करते हुए नारेबाजी की। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पदों के आवंटन, ओएमआर शीट में हेरफेर, पैसे और पैरवी के आधार पर नियुक्तियों सहित युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। युवाओं ने विवादित परीक्षाओं को रद्द कर सीबीआई जांच की मांग की।इस बीच उच्च शिक्षा संस्थानों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर तुरंत नियुक्ति शुरू करने की भी मांग की। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी ने कहा कि राज्य के लाखों युवा वर्षों से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं ने उनका विश्वास कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में हुई सभी विवादित नियुक्तियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिले।

हजारीबाग पुलिस को मिला 30 नया चार पहिया वाहन,अपराध नियंत्रण और गश्ती को मिलेगी मजबूती

हजारीबाग (एजेंसी) : हजारीबाग पुलिसिंग को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण करने के लिए झारखंड सरकार ने 30 नया चार पहिया वाहन उपलब्ध कराया है। हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने सभी गाड़ी को जरूरत के अनुसार विभिन्न थाने को उपलब्ध कराया गया है।पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम का आयोजन कर गाड़ी विभिन्न स्थानों को उपलब्ध कराया गया है।हजारीबाग एसपी ने इस दौरान सभी गाड़ियों का विधिवत पूजा भी किया।इस दौरान एसपी अमन कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा के नेतृत्व में हजारीबाग जिले को पुनः 30 वाहन मिले हैं. जिससे हजारीबाग जिले की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृद्ध करने में मजबूती मिलेगी।इन्होंने कहा कि कई थानों में वाहनों की कमी थी अब इससे वह कमी दूर हो जाएगी।

सीयूजे में युवा मतदाताओं को किया गया जागरूक

रांची (एजेंसी) : भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के निर्देशन में चलाए जा रहे न्यू वोटर्स अभियान के अंतर्गत बुधवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड (सीयूजे) के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की ओर से युवा मतदाताओं में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।मुख्य वक्ता राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग की प्राध्यापक डॉ राजर्षि पाधी ने कहा कि प्रत्येक पात्र युवा को अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराना चाहिए। मतदान सिर्फ एक अधिकार ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।कार्यक्रम की प्रस्तावना व संचालन विश्वविद्यालय के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के नोडल अधिकारी डॉ शशांक कुलकर्णी ने किया। उन्होंने कहा कि झारखंड का इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब विश्वविद्यालय के प्रत्येक युवा मतदाता तक लोकतांत्रिक जागरुकता पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रव्यापी जन-जागरुकता अभियान है, जिसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी भारत के लोकतंत्र और अधिक सशक्त बनाएगी।

कार्यक्रम का समापन राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग के प्राध्यापक डॉ संजय कुमार अग्रवाल के धन्यवाद ज्ञापन एवं प्रेरक संबोधन के साथ हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सजग व जागरूक रहने और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता की और मतदाता पंजीकरण व लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के आयोजन में डॉ प्रीति सिंह व डॉ देवाशीष का सहयोग रहा।

ट्रूथ पर्थ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक कुमार भारती के द्वारा डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, भास्कर प्रीटिंग प्रेस गोविंदपुर मेन रोड, अशोक नगर के.जी. आश्रम, धनबाद (झारखंड) से मुद्रिक एवं नियर भाटिया शिव मंदिर, गांधी नगर धनबाद से प्रकाशित फोन नं. 7004605076, 9852421580
संपादक:- रवि रंजन * इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं सम्पादन हेतु पी आर बी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उतरदायी। ई. मेल:-truthpath941@gmail.com आर. एन. आई.नंबर .-JHAHIN/2023/90593

धनबाद कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का हुआ उद्घाटन,सात को होगा समापन

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : धनबाद के पुलिस केंद्र में पुलिस सभागार में कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2026 का आयोजन किया गया है। यह पुलिस मीट 5 अगस्त से 7 अगस्त तक किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी शैलेन्द्र कुमार सिन्हा शामिल हुए, जिले के एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी मो एस याकूब , डीएसपी प्रकाश सोय , डीएसपी साइबर प्रदीप साव, सीआईडी के वरीय पदाधिकारी, एफएसएल टीम के पदाधिकारी एवं जिले के थानों प्रभारी,सब इंस्पेक्टर,इंस्पेक्टर और आरक्षी शामिल हुए । आईजी शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने पुलिस ड्यूटी मीट की घोषणा की और इस मौके पर पौधारोपण भी किया। आईजी शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने कहा कि अल्टीमेटली ये नेशनल लेवल पर होता है लेकिन हर स्टेट में रेंज में पुलिस ड्यूटी मीट होती है इसके विनर स्टेट पुलिस मीट में भाग लेते है और जो स्टेट पुलिस मीट के विनर होते है वे नेशनल पुलिस मीट में पार्टिसिपेट करते है।ये हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसका ही पार्ट है।इसमें विभिन्न सब्जेक्ट्स होते है जिनमें फोटोग्राफी से लेकर साईंटफिक फील्ड इंवेस्टिगेशन, लिफ्टिंग,पैकिंग, फॉरवर्डिंग।ये इन्वेस्टिगेशन को एन्हांस करता है

और इसको कंडक्ट करने का काम हमारी सीआईडी और फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेट्री करती है। परीक्षक मंडल जो है उसमें सीआईडी और एफ एस एल के लोग होते है और अगर किसी को कुछ इश्यू है तो उसका समाधान करते है और जो इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करते है उन्हें हम प्राइज देते है। आईजी शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने कहा कि हम प्रयासरत है हमारी टीम काम कर रही है ताकि हम सोसायटी को अच्छा परफॉर्म करके दे सके और अगर जो लोग है जिले के प्रक्षेत्र के अगर वो सेटिस्फाइड है तो हम सेटिस्फाइड है।वही एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि धनबाद में तीन दिवसीय पुलिस मीट का आयोजन किया गया है जिसमें हम सभी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऑगेर्नाइज्ड क्राइम के प्रति हम जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में उसको समझाएंगे।

सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रारूप मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद बुधवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। जिले के सभी छह क्षेत्रों सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी एवं बाघमारा के प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। प्रारूप मतदाता सूची के आधार पर दावा और आपत्ति दायर किया जा सकता है। अगर किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची में नहीं है या वोटर लिस्ट में अनमैप्ड की सूची में है तो वोटर अगले एक माह तक दावा और आपत्ति दायर कर सकते हैं। इसके लिए वोटरों को कुछ आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन जमा करना होगा। इधर जिला प्रशासन की ओर से स्कूल कॉलेजों में चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति करने के लिए समय निर्धारित है। उन्होंने मतदाताओं को समय पर अपने दस्तावेज के साथ दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। 3 अक्टूबर तक नोटिस सत्यापन तथा दावों एवं आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। जबकि 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक-एक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ना और मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे इस 'दावा एवं आपत्ति' चरण के दौरान अपनी मतदाता संबंधी जानकारियों की जांच कर लें तथा आवश्यकतानुसार समय सीमा के भीतर संबंधित बीएलओ के पास अपना आवेदन दर्ज कराएं।

संक्षिप्त खबरें

प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाने का मामला, एबीवीपी ने दर्ज कराई शिकायत

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : शहर के एसएसएलएनटी महिला कॉलेज रोड स्थित नगर निगम द्वारा छात्राओं के लिए बनाए गए शेल्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाए जाने का मामला सामने आया है। पोस्टर में एके-47 राइफल की आकृति बनाई गई थी तथा प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखी गई थीं। घटना की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पोस्टरों को हटाकर विरोध जताया।इसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता धनबाद थाना पहुंचे और पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस को सौंपी। छात्र नेता अंशु तिवारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एसएसएलएनटी कॉलेज के बाहर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पोस्टरों को हटाया।अंशु तिवारी ने कहा कि परिषद की टीम आसपास के कॉलेज परिसरों और सार्वजनिक स्थलों का भी निरीक्षण करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं अन्य स्थानों पर भी इस तरह के पोस्टर तो नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसे पोस्टर मिलेंगे, उन्हें तत्काल हटाया जाएगा।एबीवीपी कार्यकताओं ने आशंका जताई है कि इस घटना के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ हो सकता है। वहीं, कुछ कार्यकताओं ने कोकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर भी संदेह व्यक्त किया है। हालांकि, पुलिस ने किसी भी संगठन या व्यक्ति की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है। शिकायत मिलने के बाद धनबाद थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टर लगाने वालों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैंक मोड़ के शांति भवन में बिजली मीटर में भीषण आग, दमकल की तत्परता से टला बड़ा हादसा

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : धनबाद के बैंक मोड़ स्थित शांति भवन में बिजली मीटर में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगते ही मीटर से धुआं और चिंगारियां निकलने लगीं, जिससे बिल्डिंग में रहने वाले लोग घबराकर बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया।शांति भवन के लोगों ने आरोप लगाया कि बिल्डिंग में अग्निशमन यंत्र और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं।प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। घटना के बाद कुछ समय के लिए इलाके की बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। हालांकि दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की सतर्कता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

सरकारी राशि गबन के मामले में झरिया के पूर्व बीडीओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : धोखाधड़ी कर सरकारी राशि का घोटाला करने के मामले में झरिया के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी विभाष चंद्र ठाकुर के मामले की सुनवाई बुधवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष की अदालत में हुई। आरोपी काफी दिनों से अदालत में हाजिर नही हो रहे थे और उनकी ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व आवेदन भी नही दिया जा रहा था। जिसके कारण अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आरोपी बीडीओ का बंधपत्र को खारिज करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी के उपस्थिति के लिए अगली तारीख 24 सितंबर 2026 निर्धारित कर दी है। बताते चलें कि विभाष चंद्र ठाकुर जब झरिया में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे तब उनके खिलाफ सरकारी राशि गबन करने का आरोप लगा था। निगरानी की टीम ने इसकी जांच कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। निगरानी ने जांच के बाद आरोप सत्य पाते हुए उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था।

बेलगड़िया के छात्रों को मिला आइआइटी आइएसएम में निः शुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का अवसर

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद :धनबाद जिला प्रशासन तथा बैंक ऑफ इंडिया सोशल फाउंडेशन की पहल से बेलगड़िया के युवाओं को उन्नत डिजिटल एवं व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से 'डी-युवा' (धनबाद यूथ अपग्रेडेशन थ्रू वोकेशनल एंड एडवांस्ड डिजीटल स्कील्स) कार्यक्रम की शुरूआत आइआइटी (आइएसएम) में हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, आइआइटी (आइएसएम) के प्रोफेसर धीरज कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर दिनेश प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि बेलगड़िया के युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने का यह स्वर्णिम अवसर है। इस योजना को धरातल पर उतारने के जिला प्रशासन एक साल से प्रयासरत था। आइआइटी (आइएसएम) जैसे संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना बेलगड़िया के युवाओं के लिए गौरवशाली क्षण है। सभी युवाओं को इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि भू-धंसान एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्र से बेलगड़िया शिफ्ट हुए युवा को अच्छी व्यवस्था देने के लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। यह उसकी एक शुरूआत मात्र है। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उपायुक्त ने कहा कि प्रतिवर्ष 900 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण 3 वर्ष के लिए रहेगा। जिसे कंप्यूटर में जितना आता है वहीं से कोर्स की शुरूआत होगी। बेलगड़िया के युवाओं के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जिले के युवाओं, विशेष रूप से बेलगड़िया के युवाओं, को आधुनिक तकनीक, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एंट्री और ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा साइंस, पायथन-आधारित डेटा क्यूरेशन और एनोटेशन व वेब डेवलपमेंट शामिल हैं। डिजिटल कौशल में सक्षम बनाकर उन्हें भविष्य के रोजगार एवं अवसरों के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको आधुनिक कंप्यूटर लैब और विशेषज्ञ मार्गदर्शकों द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनमें कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा।

कैंप में हाथों-हाथ मिले जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : पूर्वी टुंडी अंचल अधिकारी सुरेश प्रसाद वर्णवाल की देखरेख में मोहलीडीह पंचायत भवन में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह अभियान 3 अगस्त से 7 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों और स्थानीय ग्रामीणों को त्वरित सेवा प्रदान करना है। कैंप के दौरान अंचल निरीक्षक चंदन कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी नवीन कुमार सिन्हा और कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र कुमार ने आवेदनों की तुरंत ऑन द स्पॉट जांच की। दस्तावेज सही पाए जाते ही प्रमाण पत्र जारी कर प्रिंट आउट आवेदक को सौंप दिया गया। शिविर में पहुंचे एक स्थानीय युवक को महज 2 घंटे के भीतर जाति प्रमाण पत्र मिल गया। त्वरित सेवा से खुश होकर युवक ने अन्य ग्रामीणों और छात्र- छात्राओं से अपील की कि वे इस कैंप का लाभ उठाकर अपने आवश्यक दस्तावेज तुरंत बनवाएं। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस पारदर्शी प्रक्रिया से छात्रों का समय और पैसा दोनों बचेगा, जिससे उन्हें शैक्षणिक एवं छात्रवृत्ति से जुड़े कार्यों में आसानी होगी। मौके पर मोहलीडीह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संतलाल बाबा, आजसू नेता काजल कुमार, वार्ड सदस्य, स्थानीय ग्रामीण, छात्र- छात्राएं और उनके अभिभावक मौजूद रहे। सभी ने जिला प्रशासन की इस त्वरित व जनहितैषी पहल के लिए आभार व्यक्त किया।

शिक्षक दो, शिक्षा बचाओ : मास्टर की मांग को लेकर डीसी कार्यालय की सीढ़ियों पर बैठे स्कूली छात्र

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : धनबाद जिला प्रशासन भले ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बड़े-बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन गोमो के गुनघसा माध्यमिक विद्यालय, तोपचांची की तस्वीर इन दावों की हकीकत बयां करती है। स्कूल में वर्षों से सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे 264 बच्चों की पढ़ाई चल रही है। इसी समस्या को लेकर सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और डीसी कार्यालय की सीढ़यों पर बैठकर धरना दिया। उनकी मांग थी स्कूल में जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।गोमो स्थित गुनघसा माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राएं उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। बच्चे स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी से नाराज थे। उनका कहना था कि कक्षा एक से आठ तक कुल 264 छात्रों की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक–मानस सर–के भरोसे चल रही है। ऐसे में नियमित पढ़ाई संभव नहीं हो पा रही है। बच्चे डीसी से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी।छात्रों ने बताया कि

कई कक्षाओं की पढ़ाई उन्हें स्वयं करनी पड़ती है और सप्ताह में केवल एक बार ही शिक्षक उनकी कक्षा ले पाते हैं। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य श्यामल मंडल ने कहा कि वर्षों से शिक्षक की नियुक्ति की मांग जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल के एकमात्र शिक्षक मानस ने भी माना कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ सभी कक्षाओं को पढ़ाना बेहद कठिन है।मामले पर जिला शिक्षा अधीक्षक शालिनी डूंगडूंग ने कहा कि स्कूल में शिक्षकों की कमी की जानकारी उन्हें पहले ही दी गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 अगस्त से पहले दो सहायक शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। यदि नियमित नियुक्ति संभव नहीं हुई तो डेपुटेशन पर दो शिक्षकों को भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने बच्चों को समाहरणालय लाने के मामले में स्कूल से जवाब भी तलब करने की बात कही।एक ओर शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षक की मांग को लेकर बच्चों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि 15 अगस्त से पहले प्रशासन अपना वादा कितना पूरा कर पाता है।

धनबाद में भूधसान का कहर जारी,6 घर जमींदोज, दूसरे दिन शुरू हुआ राहत-बचाव कार्य

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र स्थित सेलेक्टर गोविंदपुर में भूधसान ने एक बार फिर लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। मंगलवार शाम हुई घटना में छह घर जमीन में समा गए। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन उनका सामान मलबे में दब गया। लगातार बारिश ने प्रभावित परिवारों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। घटना के दूसरे दिन बुधवार को बीसीसीएल और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। वहीं, स्थानीय लोगों में बीसीसीएल और जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी है। प्रभावित परिवार सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की मांग कर रहे हैं और बेलगढ़िया जाने से इनकार कर रहे हैं।

मंगलवार देर शाम सेलेक्टर गोविंदपुर में अचानक भूधसान होने से छह घर देखते ही देखते जमीन में समा गए। घटना के समय घरों में मौजूद परिवार किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में

सफल रहे। हालांकि घरों में रखा सामान मलबे में दब गया। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रभावित परिवारों को पूरी रात खुले आसमान और रिश्तेदारों के यहां शरण लेकर गुजारनी पड़ी। लोगों का आरोप है कि घटना की रात न तो बीसीसीएल और न ही जिला प्रशासन की ओर से तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया।

बुधवार सुबह बीसीसीएल के अधिकारी, रेस्क्यू टीम और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाघमारा के अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें जल्द सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश बीसीसीएल अधिकारियों को दिए। इस बीच प्रभावित लोग मलबे से अपना बचा-खुचा सामान निकालने में जुटे रहे। इलाके में कई जगह जमीन में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे आसपास रहने वाले करीब दो दर्जन परिवारों में दहशत का माहौल है।बीसीसीएल के सेफ्टी ऑफिसर ने भी माना कि सेलेक्टर गोविंदपुर अब डेंजर जोन बन चुका है और यहां रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि मामले की सूचना बीसीसीएल के वरीय अधिकारियों को दे दी गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि रातभर कोई ठीक से सो नहीं सका। सभी परिवार अपने-अपने रिश्तेदारों के यहां शरण लेने को मजबूर हुए। लोगों ने मांग की कि उन्हें नजदीक के सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए ताकि उनकी जान-माल सुरक्षित रह सके।इधर बाघमारा विधायक के समर्थकों ने भी मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उनका कहना है कि विधायक ने जिला प्रशासन और बीसीसीएल अधिकारियों से सभी प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की है। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी कराई गई है। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग जल्द स्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।सेलेक्टर गोविंदपुर में भूधसान के बाद हालात अब भी सामान्य नहीं हैं। जमीन में लगातार दरारें बढ़ रही हैं और दो दर्जन से अधिक परिवार हर पल अनहोनी के डर में जी रहे हैं। प्रशासन ने राहत और पुनर्वास का भरोसा तो दिया है, लेकिन प्रभावित परिवारों की मांग है कि उन्हें जल्द स्थायी और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से उनकी जान बचाई जा सके।

भाजपा मनईटांड़ मंडल की बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर अंतर्गत मनईटांड़ मंडल की मासिक बैठक बुधवार को मंडल अध्यक्ष इंद्रभूषण कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठनात्मक एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक रणनीति बनाई गई। बैठक में विशेष रूप से शक्ति केंद्र एवं बूथ समितियों को अद्यतन एवं सशक्त बनाने, आगामी 10 अगस्त 2026 से प्रारंभ होने वाले हर घर तिरंगा अभियान तथा मंडल स्तर पर भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित करने को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। साथ ही पिछले माह संपन्न हुए संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उनकी सफलता एवं कमियों पर चर्चा की गई तथा आगामी कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी एवं ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया। मंडल प्रभारी पंकज सिन्हा ने कहा कि, संगठन की सबसे बड़ी शक्ति हमारे बूथ और शक्ति केंद्र हैं। आगामी हर घर तिरंगा अभियान एवं तिरंगा यात्रा को जन-जन की सहभागिता से ऐतिहासिक बनाकर राष्ट्रभक्ति का संदेश प्रत्येक घर तक पहुंचाना हम सभी कार्यकताओं की जिम्मेदारी है। जिला मंत्री मौसम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यक्रम संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का माध्यम है। सभी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा, अनुशासन एवं समर्पण के साथ आगामी कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने हेतु अभी से जुट जाएं। वहीं मंडल प्रवासी मिल्टन पार्थसारथी ने कहा कि संगठन की सफलता कार्यकताओं की सक्रियता, समर्पण एवं समन्वय पर निर्भर करती है। प्रत्येक बूथ तक संगठन को मजबूत करते हुए आगामी सभी कार्यक्रमों को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कार्यकताओं को पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना होगा। बैठक में उपस्थित सभी कार्यकताओं ने आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पूर्ण समर्पण एवं सक्रियता के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। बैठक में मुख्य रूप से किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल सिन्हा, मंडल महामंत्री कामदेव कुमार, दिवेश कुमार, दीपक कुमार गुप्ता, अजीत शर्मा, अजय कुमार जीराखान सिंह, बिपिन लाला, अजय दुबे, राजीव रंजन, मोंटी कुमार, सुनील पांडे, रीना गुप्ता सहित सैकड़ों पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

शहरी क्षेत्र में शुरू होंगे 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिर

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : 15 वें वित्त आयोग की राशि की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक की गई। डीसी ऑफिस सभागार में हुई बैठक में धनबाद के शहरी क्षेत्र में 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने के लिए वार्ड पार्षदों से स्थल चिह्नित कर प्रस्ताव देने का आग्रह किया गया गया। डीसी ने बैठक की अध्यक्षता की। डीसी ने सभी पार्षदों को अपने-अपने वार्ड में सरकारी भवन की उपलब्धता का प्रस्ताव देने का अनुरोध किया। उपायुक्त ने कहा कि सरकारी भवन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करना सबसे उपयुक्त रहेगा। यदि सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है तो पार्षद अन्य स्थल भी चिन्हित कर सकते हैं। बैठक में डीसी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहरी स्वास्थ्य केंद्र को पॉलीक्लिनिक के रूप में विकसित करने, विशेषज्ञ चिकित्सक बहाल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित

किया। डीसी ने ग्रामीण क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नए भवनों की समीक्षा की। साथ ही स्वास्थ्य उप केंद्रों में रिपोर्टिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट लगाने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान पार्षद ने हाई स्कूल 5भूली को प्लस टू करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि प्लस टू स्कूल नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में क्षेत्र के छात्रों को दूर के प्लस टू स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। उपायुक्त ने उनसे लिखित में प्रस्ताव देने को कहा। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने सभी पार्षदों से शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। बैठक में उप विकास आयुक्त सन्नी राज, सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री सुशांत मुखर्जी, डीपीएम प्रतिमा कुमारी नगर निगम के प्रतिनिधि, वार्ड पार्षद शोभा देवी, अरुणा कुमारी, उर्मिला मंडल, सरिता सिंह, प्रिय रंजन, मुनीलाल रबिदास, रीना देवी, मो अलिम अंसारी, रीना महतो, विकास रंजन, मीनाक्षी सिंह, कल्पना महतो, सुमन देवी, साहेब राम हेम्ब्रेम, संजू देवी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

संक्षिप्त खबरें

विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची के प्रारूप का हुआ प्रकाशन,मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचेःउपायुक्त

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : भारत निर्वाचन आयोग के निदेशार्नुसार संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बुधवार को राज्य सहित रांची जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है।उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने रांची जिला के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे प्रकाशित मतदाता सूची के प्रारूप में अपना नाम, पता एवं अन्य विवरण का अवश्य मिलान कर लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि, नाम छूट जाना अथवा अन्य आवश्यक संशोधन की आवश्यकता हो तो निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करें।उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही एवं अद्यतन रूप में दर्ज होना आवश्यक है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे स्वयं अपना नाम जांचने के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों का नाम भी मतदाता सूची में सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता होने पर समय पर दावा एवं आपत्ति दर्ज कराएं।उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करें तथा दावा एवं आपत्ति से संबंधित सभी आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करें।

मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक, सहयोग की अपील

पलामू (एजेंसी) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के अवसर पर जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी राजनीतिक दलों से सक्रिय सहयोग की अपील की।उपायुक्त ने बताया कि जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के कुल 2032 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 14,99,296 मतदाता हैं, जिनमें 7,78,456 पुरुष, 7,20,839 महिला एवं 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। साथ ही 2,65,651 एसएसडीएफ तथा 3,46,596 एनोमलाइज एलेक्ट्रस को नियमानुसार नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि 05 अगस्त से 04 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान जिन मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में नहीं है, वे निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं किसी नाम में त्रुटि, स्थानांतरण, विलोपन अथवा अन्य संशोधन के लिए भी निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपलब्ध रहेंगे तथा मतदाता पंचायत भवन, नगर निकाय कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय एवं सीईओ झारखंड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन किया जा सकता है।बैठक में बताया गया कि निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 08 एवं 09 अगस्त तथा 22 एवं 23 अगस्त को विशेष दावा-आपत्ति शिविर आयोजित किए जाएंगे। 15 अगस्त को ग्राम सभाओं के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा तथा 25 अगस्त से 04 सितंबर तक होम-टू-रोल वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।उपायुक्त श्री शेखावत ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने तथा अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाता समय पर अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

7 एवं 8 अगस्त को जमशेदपुर में आयोजित आजसू का राज्य स्तरीय युवा अधिवेशन की तैयारियां अंतिम चरण में

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची (एजेंसी) : आजसू पार्टी के युवा प्रकोष्ठ द्वारा 7 एवं 8 अगस्त को जमशेदपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय युवा अधिवेशन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। अधिवेशन को ऐतिहासिक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए संगठन स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। राज्य के सभी जिलों से बड़ी संख्या में युवा प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।अधिवेशन के प्रथम दिन कार्यक्रम का शुभारंभ वीर शहीदों को श्रद्धांजलि एवं राष्ट्रीय गान के साथ होगा। इसके बाद झारखंड आंदोलन की विरासत, युवाओं की भूमिका, वर्तमान चुनौतियों और राज्य के भविष्य की दिशा पर विभिन्न विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे।द्वितीय दिवस का शुभारंभ अमर शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया जाएगा। इसके उपरांत आयोजित खुले सत्र में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी एवं युवा प्रतिनिधि राज्य और राष्ट्र से जुड़े समसामयिक विषयों पर अपने विचार रखेंगे। अधिवेशन के समापन पर युवा संकल्प एवं विभिन्न प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।आजसू पार्टी ने राज्य के सभी जिला एवं प्रखंड पदाधिकारियों तथा युवा कार्यकताओं से अपील की है कि वे समय पर जमशेदपुर पहुंचकर अधिवेशन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। यह अधिवेशन झारखंड के युवाओं के विचार, नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक शक्ति को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।

डीसी का निर्देशः स्वतंत्रता दिवस समारोह की समस्त तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने समाहरणालय ब्लॉक-ए सभागार में मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को समारोह की सफलतापूर्वक तैयारी एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उप विकास आयुक्त संजय भगत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गौरव गोस्वामी, प्रशिक्षु आईएएस सुश्री आस्था शरण, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी, ए डी एम नक्सल सुदर्शन मुर्मू, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय, जिला शिक्षा पदाधिकारी वसिम अहमद, परियोजना निदेशक मनीषा तिर्की, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार, नजारत उप समाहर्ता रांची, डॉ. सुदेश कुमार, जिला जन संपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय, उप निर्वाचन पदाधिकारी बिवेक कुमार सुमन, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, सहायक प्रशासक रांची नगर निगम, पथ प्रमंडल 1, कार्यपालक अभियंता भवन, पेय जल, सर्जेन्ट मेजर, जिला अग्निशमन पदाधिकारी एवं सम्बंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की समस्त तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएं, ताकि कार्यक्रम गरिमापूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल को निर्देश दिए गए कि आगंतुकों के लिए मैदान के दाईं एवं बाईं ओर वाटरप्रूफ पंडाल/गैलरी तथा कुर्सियों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मैदान का समतलीकरण, बैरिकेडिंग तथा मंच एवं साउंड बॉक्स के लिए आवश्यक टॉवर निर्माण का कार्य भी समय से पूरा किया जाए।जिला नजारत उपसमाहर्ता को मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम तैयार करने, आयोजन स्थल पर मुख्य मंच की व्यवस्था तथा आमंत्रित अतिथिगणों के बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, रांची को विद्युत व्यवस्था तथा साउंडप्रूफ जनरेटर की व्यवस्था को अंतिम रूप देने और पूर्ण तैयार रखने का निदेश दिया गया।कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, वितरण प्रमंडल गोंडा को कार्यक्रम स्थल पर पेयजल आपूर्ति, वीआईपी टॉयलेट की व्यवस्था तथा परेड पूर्वाभ्यास में भाग लेने वाले कैडेटों के लिए मोरहाबादी मैदान में अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मोरहाबादी की ओर जाने वाली सड़कों की मरम्मत एवं साफ-सफाई, चिकित्सा मेडिकल कैंप तथा अग्निशमन की व्यवस्था को लेकर भी पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी गंभीरता एवं तत्परता से करें तथा सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूर्ण कर लें, ताकि समारोह भव्य एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।यह बैठक स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को सुदृढ़ एवं समन्वित बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई।जानकारी हो की इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में कुल 14 प्लाटून इसमें हिस्सा लेंगे अन्य राज्य से इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में ओडिशा पुलिस भी शामिल होने की सूचना है।

केंद्र सरकार विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ शहरी अवसंरचना को उन्नत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैः संजय सेठ

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुधवार को नई दिल्ली के अफ्रीका एवेन्यू स्थित डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित मल्टी-लेवल कार पार्किंग सुविधा के उद्घाटन के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा, शहरी अवसंरचना के विकास/उन्नयन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है।इस परियोजना को कार्यालय में पार्किंग की समस्या को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि महानगरों में, जहां जमीन एक दुर्लभ संसाधन है, बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं का समाधान उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से ही संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की पहल से कार्यस्थल की कार्यक्षमता बढ़ती है और पारंपरिक तकनीकों से आधुनिक और उन्नत तकनीकों की ओर बदलाव होता है।समयबद्ध तरीके से परियोजना को पूरा करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी के प्रयासों की सराहना करते हुए संजय सेठ ने एमपी फ्लैट्स, कर्तव्य भवन और एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव जैसी अन्य नवनिर्मित इमारतों की गुणवत्ता, सुविधा और सौंदर्य की भी प्रशंसा की, जिनका निर्माण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया था।इस 14 मंजिला बहुस्तरीय पार्किंग में उपलब्ध भूमि पर अधिकतम पार्किंग स्थान बनाने के उद्देश्य से पूर्णतः स्वचालित रोबोटिक (डॉली) तकनीक का उपयोग किया गया है। 45 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह सुविधा पारंपरिक पार्किंग की तुलना में स्थान उपयोग में 60% अधिक कुशल है। इस सुविधा में सीसीटीवी निगरानी और अग्नि सुरक्षा प्रणाली भी लगी हुई है। इस तकनीक के उपयोग से लिफ्ट लॉबी में प्रवेश करने के बाद न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और शून्य वाहन उत्सर्जन सुनिश्चित होता है।

पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के आरोप में छात्रों ने किया प्रदर्शन

रांची (एजेंसी) : झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के द्वारा ली गयी पूर्ववर्ती परीक्षा में धांधलियों का आरोप लगाकर वाम छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) के साथ ही डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवायएफआइ) ने संयुक्त रूप से प्रतिरोध रैली आयोजित की। यह रैली अभ्यर्थियों के द्वारा किये जा रहे आंदोलन के समर्थन में की गयी।रैली की शुरूआत रांची विश्वविद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंची, जहां यह एक छात्र सभा में तब्दिल हो गयी।सभा में बड़ी संख्या में छात्र-युवा और कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के प्रति एकजुटता जताई और सरकार द्वारा छात्रों से वार्ता नहीं करने पर संघर्ष को और व्यापक किए जाने का आह्वान किया। सभा की अध्यक्षता बुधराम उरांव ने की। एसएफआई की ओर से संयोजक दानिश, अमन, सोनाली और ओजस्वी राज ने छात्रों के सवाल पर संबोधित किया।अपने वक्तव्य में उन्होंने जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों की जायज मांगों, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। डीवाइएफआइ की ओर से राज्य संयोजक मोहन मंडल ने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्रों - युवाओं के आन्दोलन में सरकार चुप्पी साधे हुए है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार की भी संलिप्तता इसमें है।

प्रारूप मतदाता सूची जारी, चार सितंबर तक दर्ज करायें दावा-आपत्ति अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सात अक्तूबर को होगा

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पांच अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन हो गया।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की मौजूदगी में इसका प्रकाशन हुआ। मौके पर श्री कुमार ने प्रकाशित मतदाता सूची के बारे में जानकारी दी।उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मतदाताओं के लिए प्रारूप निर्वाचक नामावली (ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) व एएसडीडी लिस्ट को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराया गया है। श्री कुमार ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों के नाम छूट गये हैं, वे पांच अगस्त से चार सितंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियों की अवधि में घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर अपना नाम पुनः मतदाता सूची में शामिल करा सकते है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सात अक्तूबर को किया जायेगा। एसआइआर के दौरान शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए हेल्प डेस्क, कॉल सेंटर, इसीआइनेट, वीएसपी और एनजीएसपी पोर्टल के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी गयी। एनजीएसपी पर प्राप्त 4,558 शिकायतों में से अधिकांश का निबटारा कर दिया गया है।इस तरह इस मामले में यह राज्य अव्वल रहा है।श्री कुमार ने बताया कि मतदाता अपना नाम ईसीआईनेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते हैं।प्रारूप निर्वाचक नामावली एवं एएसडीडी सूची के लिए अलग-अलग लिंक उपलब्ध कराये गये हैं।सीइओ ने बताया कि ऑफलाइन माध्यम में प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रारूप निर्वाचक नामावली तथा एएसडीडी सूची की प्रकाशित प्रतियां उपलब्ध रहेंगी। दोनों सूचियों की एक-एक प्रति संबंधित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को भी उपलब्ध करायी जायेगी।मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पेन ड्राइव के माध्यम से भी यह दिया जायेगा। इसके साथ ही सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालयों में भी यह उपलब्ध रहेंगी।श्री कुमार ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य में 2,389 नये मतदान केंद्र स्वीकृत किये गये हैं। 68 केंद्रों का विलय किया गया। इसके बाद मतदान केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 31,892 हो गयी है।आयोग का उद्देश्य प्रत्येक मतदाता को दो किलोमीटर के भीतर मतदान केंद्र उपलब्ध कराना है।एसआइआर अभियान में राज्य के सभी 24 जिलों के प्रशासन, 81 इआरओ, 365 एइआरओ, 29,571 बीएलओ, 29,571 स्वयंसेवकों तथा नौ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 77,430 बूथ लेवल एजेंटों ने सक्रिय भागीदारी निभायी।

मांगों को लेकर सचिवालय में कर्मियों ने बनाया मानव श्रृंखला,छह अगस्त से 12 अगस्त तक काला बिल्ला लगा कर करेंगे काम

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : झारखंड सचिवालय सेवा संघ के बैनर तले पांच अगस्त को प्रोजेक्ट भवन व नेपाल हाउस सचिवालय में कर्मियों का जुटान हुआ।उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाया। दोनों सचिवालय में हाथों में मांगों से संबंधित स्लोगन वाला तख्ता लिये वे खड़े रहे।इस दौरान उन्होंने सचिवालय सेवा की मांगों के समर्थन में अपनी एकता व प्रतिबद्धता दिखायी। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि आंदोलन के इस चरण में संघ द्वारा किसी भी प्रकार से सरकारी कार्यों को बाधित करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।संघ के सभी सदस्य अपने नियमित कार्यों के निष्पादन के बाद आंदोलन में भाग ले रहे हैं।संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वे मुख्य रूप से उनकी सेवा को लेकर सरकार के प्रतिकूल प्रस्तावित निर्णयों को वापस लेने, उनकी सेवा के हित की रक्षा, लंबित प्रोन्नति का हल, संयुक्त व उप सचिव के पर्याप्त पदों का सृजन आदि की मांग कर रहे हैं। इसमें संघ का पक्ष सुनने की भी मांग रखा है. उन्होंने कहा कि समय-समय पर समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के समक्ष ज्ञापन, प्रतिनिधिमंडल एवं संवाद के माध्यम से समाधान का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस एवं सकारात्मक पहल नहीं की गई है।इसी कारण संघ को चरणबद्ध आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ा है।अब आंदोलन के अगले चरण में छह अगस्त से 12 अगस्त तक सचिवालयच सेवा के सभी सदस्य काला बिल्ला लगा कर काम करेंगे।इसके बाद भी मांगों पर कुछ नहीं हुआ, तो अगले चरण की रणनीति तैयार की जायेगी. इसके तहत कलमबंद आंदोलन, सामूहिक अवकाश व हड़ताल जैसे कदम उठाये जायेंगे।

हिंदपीढ़ी में गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने वाला नाबालिग बड़ा तालाब में डूबा, हुई मौत

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : रांची के हिंदपीढ़ी में आधा दर्जन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने वाले नाबालिग लड़का ने बुधवार को बड़ा तालाब में छलांग लगा दी, जिसे उसकी मौत हो गयी। मृतक नाबालिग हिंदपीढ़ी इलाके का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वह बुधवार की दोपहर बड़ा तालाब के पास बैठा हुआ था। इसी क्रम में उसके हाथ से कुछ चीजें तालाब में गिर गई, जिसे निकालने के लिए उसने छलांग लगा दी। काफी देर तक जब नाबालिग बाहर नहीं निकला तो आसपास मौजूद स्थानीय गोताखोर उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गए। काफी मशक्कत के नाबालिग का शव तालाब से बाहर निकाला गया।घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली और हिंदपीढ़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नाबालिग का शव अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नाबालिग नशे का आदि था। डूबने से पहले भी वह नशे की हालत में था। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।

ट्रिपल मर्डर से इलाके में दहशत,आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बोकारो (एजेंसी) : बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत नावाडीह प्रखंड में बुधवार को पूर्वाह्न एक दिल दहला देने वाली ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आई है। एक ही परिवार के तीन लोगों की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।नावाडीह थाना क्षेत्र के कुकुरलिलवा गांव में खेत जाने के दौरान जानकी महतो, उनकी पत्नी सुगिया देवी और बहू गौरी देवी पर पड़ोसी राजू सिंह ने अचानक कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में जानकी महतो और सुगिया देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल गौरी देवी को सदर अस्पताल, बोकारो ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।घटना के बाद आरोपी राजू सिंह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गांव में घूमता रहा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिटी डीएसपी मुख्यालय पवन कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी नशे का आदी था। पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुटी है।

झारखंड के छात्रों की आवाज को अनसुना करना लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य, दोनों के साथ अन्याय : अन्नपूर्णा देवी

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में आंदोलनरत छात्रों के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से तत्काल संवेदनशील एवं निर्णायक पहल करने की मांग की है।उन्होंने कहा कि झारखंड के लाखों छात्र-छात्राएँ कई दिनों से अपने भविष्य और न्यायपूर्ण अधिकारों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। यह केवल भर्ती परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास, उनके परिश्रम और उनके भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। आज चार छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हजारों छात्र न्याय की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन राज्य सरकार की संवेदनहीनता चिंताजनक है। न कोई सार्थक पहल हो रही है और न ही कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि छात्रों से संवाद करने पहुँच रहा है।उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के वे नेता, जो देशभर में छात्रों के नाम पर राजनीति करते हैं, आज झारखंड के लाखों युवाओं के आंदोलन पर मौन क्यों हैं? क्या छात्रों का दर्द भी राज्य और सरकार देखकर तय किया जाएगा? छात्रों को बरगलाने की राजनीति करने वाले राहुल गांधी का झारखंड के छात्रों के प्रति यह दोहरा आचरण दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से मांग की कि जेपीएससी जीएसएससी तथा अन्य सभी विवादित भर्ती प्रक्रियाओं की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही प्रतिबंधित एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को तत्काल निरस्त कर पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत पुनः आयोजित किया जाए, ताकि युवाओं का विश्वास बहाल हो सके।उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही इस विषय को गंभीरता से उठाती रही है। जिसके परिणाम स्वरूप सीआईडी ने कार्रवाई शुरू की और जेपीएससी अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा।

संक्षिप्त खबरें

दुर्घटना में मृत दो श्रमिकों के आश्रितों को 30.91 लाख रुपये की दी गई क्षतिपूर्ति राशि

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत उपश्रमायुक्त ने दिलाया आर्थिक संबल

गया जीः दुर्घटना में मृत दो श्रमिकों के आश्रितों को 30.91 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कराया गया। गया जिला उपश्रमायुक्त की पहल पर दुर्घटना में मृत हुए दिलीप पासवान के आश्रितों को 14.50 लाख रुपये प्रदान किए गए। यह राशि उनकी पत्नी एवं चार नाबालिग बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में दी गई ताकि विपरीत परिस्थितियों में उन्हें संबल मिल सके।वहीं दुर्घटना में मृत सिन्टू कुमार के पिता सुरेंद्र प्रसाद को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत 16.41 लाख रुपये का भुगतान कराया गया।उपश्रमायुक्त ने बताया कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कानून है। इसके तहत कार्य के दौरान दुर्घटना, गंभीर चोट, स्थायी विकलांगता अथवा मृत्यु होने पर नियोक्ता द्वारा पीड़ित कर्मचारी या उसके आश्रितों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है। इससे प्रभावित परिवारों को कठिन समय में आर्थिक सहारा मिलता है।

फतेहपुर में सुशासन की पहल: सहयोग शिविर में 135 मामलों का त्वरित निष्पादन

फतेहपुर (गया जी):फतेहपुर प्रखंड की चरोखरी और बारा पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन तथा नगर पंचायत फतेहपुर में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर ग्रामीणों के लिए सुशासन का प्रभावी माध्यम साबित हुआ। एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराकर लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की। शिविर में पहले से लंबित 50 आवेदनों का निष्पादन किया गया, जबकि विभिन्न विभागों से संबंधित 85 नए आवेदन प्राप्त हुए। सभी नए आवेदनों को त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इन मामलों का भी शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान 50 किसानों को कृषि ऐप से जोड़ा गया, जिससे उन्हें कृषि योजनाओं, आधुनिक तकनीक और सरकारी सुविधाओं की समय पर जानकारी मिल सकेगी। बीडीओ शशिभूषण साहू ने पात्र लाभुकों के बीच राशन कार्ड वितरित किए और लंबित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र भी सौंपे। शिविर में डीसीएलआर दिलीप कुमार ध्वज, सीओ अमिता सिन्हा, बीपीआरओ प्रमोद कुमार शाह, बीईओ दिनेश कुमार राय, मुख्य पार्षद रवि कुमार, मुखिया शकुंतला देवी, मुखिया अशोक यादव, मनीष कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की पहुंच गांव स्तर तक सुनिश्चित करना और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है।

जिले में अव्वल उतरी लोधवे पंचायत, 100 पशुपालकों को मिली निःशुल्क पशु किट

457 किट में से पंचायत को मिला सबसे बड़ा हिस्सा, पारदर्शी तरीके से हुआ वितरण

फतेहपुर (गया जी)ः फतेहपुर प्रखंड की उतरी लोधवे पंचायत ने पशुपालन प्रोत्साहन योजना के तहत जिले में सबसे अधिक निःशुल्क पशु किट प्राप्त कर एक नई पहचान बनाई है। बुधवार को आयोजित वितरण कार्यक्रम में 100 चयनित पशुपालकों के बीच निःशुल्क पशु किट वितरित किए गए। मुखिया अभय कुमार यादव ने बताया कि गया जिले के लिए कुल 457 निःशुल्क पशु किट स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से उतरी लोधवे पंचायत को 100 किट का आवंटन मिला। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर किए गए समन्वित प्रयासों के कारण यह उपलब्धि संभव हो सकी। अधिकारियों ने बताया कि किट का वितरण निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्र पशुपालकों के बीच पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे छोटे और मध्यम पशुपालकों को पशुपालन गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी तथा पंचायत क्षेत्र में पशुपालन को नया प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यक्रम में जलछाजन परियोजना की डब्ल्यूडीटी अंजू सिंह, सामाजिक उत्प्रेरक श्वेता चौधरी तथा पशु चिकित्सा प्रबंधक ओम प्रकाश सिंह सहित पंचायत प्रतिनिधियों, जलछाजन परियोजना से जुड़े अधिकारियों और पशुपालन विभाग के पदाधिरियों और ग्रामीणों की उपस्थिति रही।

श्रावणी मेले को लेकर गया जंक्शन पर आरपीएफ का सघन सुरक्षा अभियान

स्टेशन परिसर की हुई चप्पे-चप्पे पर जांच,

संदिग्ध व्यक्तियों व लावारिस सामान पर रखी गई कड़ी नजर

गया जी:श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने गया जंक्शन पर विशेष सुरक्षा एवं चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य स्टेशन परिसर में विधि-व्यवस्था बनाए रखना, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाना तथा श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा का माहौल उपलब्ध कराना था।

पूर्व मध्य रेल के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त (आरपीएफ आईजी) अमरेश कुमार की मॉनिटरिंग तथा डीडीयू रेल मंडल के वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश सिंह तोमर के निर्देश पर सहायक सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आरपीएफ की विशेष टीम ने स्टेशन परिसर के विभिन्न हिस्सों में सघन जांच की। अभियान के दौरान प्लेटफॉर्म, सकुर्लेटिंग एरिया, प्रतीक्षालय, फुट ओवर ब्रिज, प्रवेश एवं निकास द्वार सहित अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से तलाशी ली गई। आरपीएफ जवानों ने यात्रियों के सामान की गहन जांच की तथा संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी। इसके साथ ही स्टेशन परिसर में लावारिस पड़े सामान और वस्तुओं की भी सावधानीपूर्वक जांच की गई, ताकि किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को समय रहते रोका जा सके। सुरक्षा कर्मियों ने यात्रियों से अपील की कि वे अपने सामान की स्वयं निगरानी रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु की सूचना तत्काल आरपीएफ अथवा रेलवे हेल्पलाइन पर दें।

अभियान के दौरान यात्रियों को रेलवे सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए गए। उन्हें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क रहने, अनजान व्यक्तियों से सावधान रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को देने के लिए जागरूक किया गया। आरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों के सहयोग से ही रेलवे परिसर को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। पूरे अभियान के दौरान किसी प्रकार की संदिग्ध अथवा आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई और चेकिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि श्रावणी मेला अवधि में गया जंक्शन सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर इसी प्रकार के विशेष सुरक्षा अभियान लगातार चलाए जाएंगे। रेलवे सुरक्षा बल ने भरोसा दिलाया कि श्रद्धालुओं एवं अन्य यात्रियों की सुरक्षित, निर्बाध और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

निर्वाचक नामावली की शुद्धता विषय पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

श्रीलंका, मॉरीशस, भूटान सहित कई देशों के प्रतिनिधि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े

पटना : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय, बिहार द्वारा चाणक्य राष्ट्रीय जय विधि विश्वविद्यालय (सीएनएलयू), पटना के सहयोग से ॹनिर्वाचक नामावली की शुद्धता विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार को चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। कार्यशाला में बिहार के राष्ट्रीय स्तर के सभी मास्टर ट्रेनर तथा राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर ने अपनी सहभागिता दी। साथ ही श्रीलंका, मॉरीशस, भूटान सहित कई देशों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। स्वागत भाषण सीएनएलयू के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय के डीन-सह-रजिस्ट्रार प्रो. डॉ. एसपी सिंह ने दिया।अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार माधव कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए त्रुटिरहित एवं अद्यतन निर्वाचक नामावली अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों तथा सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।इसके पश्चात उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने ॹनिर्वाचक नामावली की शुद्धताॹ विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने में शुद्ध निर्वाचक नामावली के महत्व को रेखांकित किया।

कार्यशाला में भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थानकाई दिल्ली के श संजय शर्मा ने विषयगत प्रस्तुति दी।

गहलौर में 17 अगस्त को दशरथ मांझी को नमन करने के लिए उमड़ेगा जनसैलाब

19वीं पुण्यतिथि पर फतेहपुर से गहलौर घाट समाधि स्थल तक निकलेगी श्रद्धांजलि यात्रा

फतेहपुर (गया जी)ः पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 17 अगस्त को फतेहपुर से गहलौर घाट स्थित उनके समाधि स्थल तक विशाल मोटरसाइकिल श्रद्धांजलि यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन की तैयारियों को लेकर बुधवार को फतेहपुर प्रखंड स्थित प्लस टू राम सहाय उच्च विद्यालय के सभा मंच पर विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न प्रखंडों के आयोजन प्रतिनिधियों और कार्यकताओं ने भाग लिया।सामाजिक संस्था मुशहर भुइया सेवा संघ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं सांसद प्रतिनिधि ई. नंदलाल मांझी ने बताया कि श्रद्धालु मानपुर-भुसंडा-बाला में एकत्रित होकर सबसे पहले दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद मोटरसाइकिल रैली मुफस्सिल और भिंडस मोड़ होते हुए गहलौर घाट स्थित पवित्र समाधि स्थल पहुंचेगी, जहां श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी प्रेम, संकल्प और अदम्य इच्छाशक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने 22 वर्षों तक अकेले पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बनाया, जिससे वजीरगंज मुख्यालय तक आवागमन सुगम हो गया। उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि आज भी पूरे समाज को संघर्ष और दृढ़ निश्चय का संदेश देती है।बैठक में विकास मांझी, ललिता देवी, श्रवण मांझी, उपेंद्र मांझी, पिंटू मांझी, अखिलेश कुमार, योगेश मांझी, दीना मांझी, नरेश मांझी, संजय भारती, मनोज मांझी, शंकर मांझी, नारायण मांझी और सुनील मांझी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गया जंक्शन से पुराने फुट ओवर ब्रिज को हटाने का काम शुरू, दिसंबर तक नया ब्रिज बनाने का लक्ष्य

एक साल से बंद था हावड़ा एंड का सबसे पुराना एफओबी,अब पुनर्निर्माण का रास्ता साफ

प्लेटफार्म-1 से 7 तक आने-जाने में यात्रियों को हो रही थी भारी परेशानी

गया जीःपूर्व मध्य रेलवे के डीडीयू रेल मंडल अंतर्गत गया जंक्शन पर पिछले करीब एक वर्ष से बंद पड़े हावड़ा एंड के सबसे पुराने फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के पुनर्निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग ने पुराने पुल को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ध्वस्तीकरण का कार्य पूरा होते ही नए एफओबी का निर्माण तेज गति से कराया जाएगा। रेलवे ने दिसंबर तक नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि

श्रावण मास के लेकर एक नंबर प्लेटफार्म पर कांवरियों और तीर्थयार्थियों की बढ़ी भीड़ के कारण एफओबी तोड़ने की कार्रवाई में व्यवधान आने से कार्य धीमी गति से हो रही है। हावड़ा एंड का यह फुट ओवर ब्रिज प्लेटफार्म संख्या-1 से 7 तक यात्रियों की आवाजाही की प्रमुख कड़ी रहा है। पुल के जर्जर होने के कारण इसे करीब एक साल पहले सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। इसके बाद यात्रियों को दूसरे फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करना पड़ रहा था जिससे विशेषकर भीड़भाड़ के समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।सुरक्षित और सुगम आवागमन के लिए बेहतर होगी व्यवस्था रेलवे अधिकारियों ने बताया कि नया फुट ओवर ब्रिज आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। इसमें यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। फुट ओवर ब्रिज के तैयार होने के बाद प्लेटफार्मों के बीच आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुगम और सुरक्षित होगा।

नया फुट ओवर ब्रिज प्लेटफार्म संख्या 1 से 8 नंबर प्लेटफार्म तक जुड़ेगा। क्योंकि गया जंक्शन पर आठ नंबर प्लेटफार्म का नया विस्तार किया गया है।

रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग का कहना है कि निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जाएगा ताकि यात्रियों को जल्द राहत मिल सके।

दानापुर इंटरसिटी में आरपीएफ का छापा, 126 कैन बीयर बरामद

फतेहपुर (गया जी) : रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सतर्क के तहत गझंडी रेलवे स्टेशन पर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस छापेमारी की। छामपेमारी ट्रेन से 126 कैन बीयर बरामद की गई। बरामद बीयर की कुल क्षमता 63 लीटर और अनुमानित कीमत 18,900 रुपये आंकी गई है। इसमें किसी की गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी है।

बताया गया कि आरपीएफ निरीक्षक दीपक कुमार के नेतृत्व में गया-कोडरमा रेलखंड पर ट्रेनों और स्टेशनों पर विशेष छापेमारी व सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान गझंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर पहुंची गाड़ी संख्या 13233 दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की जांच की गई। जांच के दौरान शौचालय के पास दो संदिग्ध ट्रॉली बैग लावारिस हालत में रखे मिले। आसपास बैठे यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी ने भी बैग पर अपना दावा नहीं किया। संदेह के आधार पर दोनों ट्रॉली बैग को मौके पर ही खोलकर जांच करने पर उसमें से 116 कैन किंगफिशर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बीयर बरामद हुई। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि ट्रेन के अल्प ठहराव के कारण पूरी बोगी की जांच नहीं हो सकी और तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। जब्त बियर की कीमत करीब 18,900 रुपए है। उन्होंने बताया कि बरामद बीयर को अग्रिम कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया। मामले की आगे की जांच की जा रही है।

बिहार की कला, संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण-संवर्धन को मिलेगी नई मजबूती

राज्य मंत्रिपरिषद ने तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी स्वीकृति

पुरातत्व निदेशालय में 12 तकनीकी पदों पर संविदा के आधार पर होगा नियोजन

पटनाः बिहार की कला, संस्कृति, पुरातात्विक एवं पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, संवर्धन और वैज्ञानिक प्रबंधन की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य मंत्रिपरिषद ने कला एवं संस्कृति विभाग से संबंधित तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रिपरिषद ने पुरातत्व निदेशालय, कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत कुल 16 तकनीकी पदों के विरुद्ध 12 पदों पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, संविदा के आधार पर नियोजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता से राज्य के पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों से संबंधित उत्खनन, अन्वेषण, सर्वेक्षण, संरक्षण, सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार, संवर्धन एवं अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी कार्यों के कुशलतापूर्वक प्रबंधन एवं संचालन में सहायता मिलेगी।इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम ॾज्ञान भारतम् मिशनॾ के अंतर्गत सर्वेक्षित पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण एवं मेटाडेटा निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल ₹6,23,68,718 (छह करोड़ तेईस लाख अड़सठ हजार सात सौ अठारह रुपये) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा एवं बौद्धिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से संचालित ज्ञान भारतम् मिशन के तहत पांडुलिपियों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, डिजिटलीकरण एवं अभिलेखीकरण किया जा रहा है। इस योजना से बहुमूल्य पांडुलिपियों को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रखने के साथ उन्हें शोधार्थियों, विद्यार्थियों, आम नागरिकों एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाने में मदद मिलेगी।

हर घर तिरंगा अभियान 2026ॾ के लिए ₹6.12 करोड़ की स्वीकृति

राज्य मंत्रिपरिषद ने कला एवं संस्कृति विभाग के ॾहर घर तिरंगा अभियान 2026ॾ के सफल आयोजन के लिए ₹6,12,00,000 (छह करोड़ बारह लाख रुपये) के व्यय को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से राज्य में अभियान के सफल आयोजन एवं इससे संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा।बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के ये निर्णय बिहार की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पांडुलिपि विरासत के संरक्षण के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे एक ओर पुरातत्व निदेशालय की तकनीकी क्षमता मजबूत होगी, वहीं दूसरी ओर बिहार की बहुमूल्य ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से संरक्षित कर व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। ॾहर घर तिरंगा अभियान 2026ॾ के माध्यम से राज्यभर में राष्ट्रीय गौरव एवं देशभक्ति की भावना को और व्यापक बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

तालाब ने छीन ली मासूम जिंदगी: सूर्य मंदिर परिसर में डूबने से 14 वर्षीय अनीश की मौत

फतेहपुर (गया जी)ः फतेहपुर थाना क्षेत्र के बड़गांव स्थित छठ पूजा सूर्य मंदिर परिसर के पास बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 11 वर्षीय बच्चे अनीश कुमार की तालाब में डूबने से मौत हो गई। अनीश मतासो पंचायत के सुंदरचक टोला निवासी पिंटू प्रजापत का पुत्र था। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया व पूरे गांव में मातम पसर गया।जानकारी के अनुसार अनीश सूर्य मंदिर के समीप तालाब के किनारे गया था। वह पानी में पैर धो रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे डूबते देख शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण तत्काल तालाब में उतर गए। काफी मशक्कत के बाद किशोर को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन के साथ ही बड़ी संख्या में लोग जुट गए। परिजनों के चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। वहीं इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। इधर, घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया भेज दिया।

गया जंक्शन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई 4.415 किलोग्राम मादक पदार्थ के साथ तस्कर गिरफ्तार

गया जीःपूर्व मध्य रेलवे के गया जंक्शन पर बुधवार को आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोश के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.415 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 22 लाख 7 हजार 500 रुपये बताई गई है। आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सह आरपीएफ आईजी अमरेश कुमार ने बताया कि सहायक सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष सर्च अभियान के दौरान यह सफलता मिली। अभियान के क्रम में आरपीएफ के सहायक उपनिरीक्षक पवन कुमार एवं उनकी टीम गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 के हावड़ा एंड स्थित फुट ओवर ब्रिज के नीचे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली गई।पूछताछ में उसकी पहचान राज मोहन पिता अर्जुन गंझु, निवासी बेलगड़ा थाना कुदा, जिला चतरा (झारखंड) के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से 4.415 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। सहायक सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह मौके पर ही विधिसम्मत कार्रवाई के बाद मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आरपीएफ ने जब्त अफीम और आरोपी को राजकीय रेल थाना गया के हवाले कर दिया। आरपीएफ की शिकायत के आधार पर जीआरपी गया में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि मादक पदार्थ की खेप कहां से लाई गई थी तथा इसे किस स्थान तक पहुंचाया जाना था। आईजी ने बताया कि इस उत्कृष्ट करवाई में शामिल टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।

संपादकीय

चढ़ावा चोरी पर हंगामा, केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार निशाने पर

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और दान चोरी के मामले में संसद और उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिसर में विपक्षी दल और समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। यह हंगामा सदन के अंदर और सदन के बाहर भी हो रहा है। विपक्षी दल इस पर चर्चा करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार इस मामले में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण हंगामा और गतिरोध प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण अब संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही भी प्रभावित हो रही है। सदन में कामकाज नहीं हो पा रहा है। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब आसंदी भी निष्पक्ष नहीं रही, वह भी निशाने पर आ गई है। संसदीय परंपराओं में यह एक ऐसी घटना है जिससे संसदीय कार्यवाही में आसंदी को लेकर जो पक्ष और विपक्ष के बीच में विश्वास होता था सदन का अध्यक्ष पक्ष और विपक्ष को जोड़ने का काम करता था, दोनों पक्षों पर विवाद होने की स्थिति में दोनों पक्षों को समझा- बुझाकर संसद और विधानसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब यह भूमिका भी समाप्त होती हुई नजर आ रही है। सदन के अध्यक्ष का निर्वाचन बहुमत के आधार पर होता है। निश्चित रूप से बहुमत सत्ताधारी पार्टी के पास होता है। यदि अध्यक्ष सत्ताधारी दल के लाभ-हानि को ध्यान में रखते हुए निर्णय करने लगेगा तो संसदीय परंपराओं को चला पाना संभव नहीं होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र शुरू हुआ। कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। निश्चित रूप से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और दान चोरी के मामले में भाजपा बचाव की मुद्रा में है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी आक्रामक मुद्रा में है। जितना यह मामला तूल पकड़ेगा उतना ही फायदा विपक्ष और नुकसान सत्तारूढ़ पार्टी को होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है। विधानसभा के अध्यक्ष ने जिस तरह से विधायकों से चंदा देने के प्रमाण पेश करने को कहा। मुख्यमंत्री के खिलाफ सपा विधायक पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। विधायक सदन के अंदर नारेबाजी कर रहे थे तब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधायक सचिन यादव को सदन से बाहर करते हुए संपूर्ण सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला यहीं तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 80 और 20 के चुनावी समीकरण को लेकर पिछले तीन दशक से राजनीति कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला भाजपा और संघ के लिए भारी पड़ रहा है।

बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलती से सीखता है।

: पी सायरस

विफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का सर्वश्रेष्ठ समय है।

: परमहंस योगानंद

सूडोकु नवताल- 7595

★★★✯☆ मध्यम

		5			8			3
	7			3	5			
3						6		
							8	5
	6			7			1	
4	2							
		1						8
			7	4			3	
6			2			7		

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7594 का हल

9	4	8	7	5	1	6	2	3
3	7	5	6	4	2	1	8	9
6	2	1	3	9	8	4	7	5
4	1	3	8	6	7	9	5	2
5	8	6	9	2	4	3	1	7
2	9	7	5	1	3	8	4	6
8	6	4	2	7	9	5	3	1
7	3	9	1	8	5	2	6	4
1	5	2	4	3	6	7	9	8

दैनिक पंचांग

6 अगस्त 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति	लग्नारंभ समय	
सूर्य	कर्क में	सिंह	06.24 बजे से
चंद्र	मेष में	कन्या	08.36 बजे से
मंगल	मिथुन में	तुला	10.47 बजे से
बुध	कर्क में	वृश्चिक	13.02 ब.से
गुरु	कर्क में	धनु	15.18 बजे से
शुक्र	कन्या में	मकर	17.23 बजे से
शनि	मीन में	कुंभ	19.09 बजे से
राहु	कुंभ में	मीन	20.42 बजे से
केतु	सिंह में	मेष	22.13 बजे से
		वृष	23.53 बजे से
		मिथुन	01.51 बजे से
		कर्क	04.04 बजे से

राहुकाल 1.30 से 3.00 बजे तक

गुरुवार 2026 वर्ष का 218 वा दिन **दिशाशूल** दक्षिण **ऋतु** वर्षा। **विक्रम संवत्** 2083 **शक संवत्** 1948 **मास** श्रावण (दक्षिण भारत में आषाढ) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** अष्टमी 18.53 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** भरणी 20.14 बजे को समाप्त। **योग** गण्ड 15.01 बजे को समाप्त। **करण** बालव 07.52 बजे तदनन्तर कौलव 18.53 बजे को समाप्त। **चन्द्रायु** 22.6 घण्टे **रवि क्रान्ति** उत्तर 16° 45' **सूर्य** दक्षिणायन **कलि अहर्गण** 1872793 **जूलियन दिन** 2461258.5 **कलियुग संवत्** 5128 **कल्पारंभ संवत्** 1972949128 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885128 **वीरनिर्वाण संवत्** 2552 **हिजरी सन्** 1448 **महीना** सफर **तारीख** 22

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
शुभ	05.54 से	07.22 बजे तक	अमृत	05.40 से	07.11 बजे तक
रोग	07.22 से	08.51 बजे तक	चर	07.11 से	08.43 बजे तक
उद्वेग	08.51 से	10.19 बजे तक	रोग	08.43 से	10.15 बजे तक
चर	10.19 से	11.47 बजे तक	काल	10.15 से	11.47 बजे तक
लाभ	11.47 से	01.15 बजे तक	लाभ	11.47 से	01.19 बजे तक
अमृत	01.15 से	02.43 बजे तक	उद्वेग	01.19 से	02.51 बजे तक
काल	02.43 से	04.11 बजे तक	शुभ	02.51 से	04.23 बजे तक
शुभ	04.11 से	05.40 बजे तक	अमृत	04.23 से	05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jagrutidaur.com, Bangalore

भाजपा के सामने क्या राजनीतिक आत्ममंथन का समय है?

लोकतंत्र में कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिनका महत्व उनके आकार से नहीं, बल्कि उनके संदेश से तय होता है। उपचुनाव सामान्यतः किसी सरकार का जनादेश नहीं माने जाते, क्योंकि वे स्थानीय परिस्थितियों, उम्मीदवारों और तत्कालीन राजनीतिक समीकरणों से भी प्रभावित होते हैं। फिर भी कई बार यही छोटे चुनाव बड़े राजनीतिक संकेत छोड़ जाते हैं। वे सत्ता को यह बताते हैं कि जनता किस बात से संतुष्ट है और किस बात से बेचैन। इतिहास गवाह है कि अनेक बार उपचुनावों ने आने वाले बड़े चुनावों की राजनीतिक दिशा का पूवार्भास कराया है।

बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनावों के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसे ही कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। विशेष रूप से बांकीपुर का परिणाम इसलिए अधिक चर्चा में है कि इसे लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा था। तीन दशकों से अधिक समय तक इस सीट पर पार्टी की लगातार मौजूदगी ने यह धारणा बना दी थी कि यहाँ भाजपा की राजनीतिक पकड़ लगभग अटूट है। ऐसे में अप्रत्याशित हार ने स्वाभाविक रूप से राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है ।उपचुनाव के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नेता नीतीश कुमार से हुई मुलाकात ने भी राजनीतिक अटकलों को बल दिया। औपचारिक रूप से इसे बिहार और पूर्वी भारत के विकास से जुड़ी सामान्य बैठक बताया गया, लेकिन राजनीति में समय का अपना महत्व होता है। जब कोई महत्वपूर्ण बैठक किसी अप्रत्याशित चुनावी परिणाम के तुरंत बाद होती है, तो उसके राजनीतिक अर्थ तलाशना स्वाभाविक हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि हर मुलाकात संकट का संकेत हो, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि चुनावी झटकों के बाद सहयोगी दलों के साथ संवाद बढ़ाना किसी भी गठबंधन सरकार की सामान्य राजनीतिक रणनीति होती है।

इसी बीच भाजपा की वरिष्ठ नेता यशोधरा राजे सिंधिया का सोशल मीडिया पर किया गया संक्षिप्त संदेश–आत्मनिरीक्षण का समय–भी व्यापक चर्चा का विषय बना। लोकतांत्रिक दलों में चुनावी समीक्षा कोई असामान्य प्रक्रिया नहीं होती। किसी वरिष्ठ नेता द्वारा आत्ममंथन की आवश्यकता पर बल देना राजनीतिक परिपक्वता का संकेत भी माना जा सकता है। विशेष रूप से तब, जब वह नेता लंबे सार्वजनिक जीवन का अनुभव रखता हो और संगठन के भीतर उसकी अलग पहचान हो। किसी भी बड़े राजनीतिक दल की शक्ति केवल चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि हार के कारणों को समझने और उनसे सीखने की क्षमता में भी निहित होती है ।दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति का स्वरूप तेजी से बदला है। अब केवल मजबूत संगठन, प्रभावशाली नेतृत्व या चुनावी प्रबंधन पर्याप्त नहीं रह गया है। मतदाता पहले की तुलना में अधिक जागरूक, अधिक अपेक्षाकारी और अधिक निर्णायक दिखाई देता है। वह राष्ट्रीय नेतृत्व का सम्मान करते हुए भी स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता, सामाजिक समीकरणों और शासन के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अलग-अलग चुनावों में अलग निर्णय लेने लगा है। यही कारण है कि आज उपचुनावों को भी राजनीतिक मनोविज्ञान की दृष्टि से गंभीरता से पढ़ा जाता है ।बिहार के संदर्भ में यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य में हाल में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद जनता की प्रतिक्रिया का यह पहला बड़ा अवसर था। किसी भी राजनीतिक परिवर्तन का वास्तविक परीक्षण चुनावी मैदान में ही होता है। सरकारें चाहे कितने भी दावे करें, अंततः मतदाता ही यह तय करता है कि वह बदलाव को स्वीकार कर रहा है या उसके प्रति संदेह रखता है। ऐसे में बांकीपुर का परिणाम केवल एक निर्वाचन क्षेत्र का फैसला नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है।

हालाँकि किसी एक उपचुनाव के आधार पर दूरगामी निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा। भारतीय राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहाँ उपचुनावों के परिणाम बाद के आम चुनावों से बिल्कुल अलग रहे हैं। इसलिए इन नतीजों को अंतिम जनादेश के बजाय एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखना अधिक संतुलित दृष्टिकोण होगा। लेकिन संकेतों की अनदेखी भी लोकतंत्र में अक्सर महँगी साबित होती है। चुनाव परिणाम कभी-कभी आँकड़ों से अधिक मनःस्थिति का परिचय देते हैं, और राजनीतिक दलों के लिए मतदाताओं की मनःस्थिति को समझना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है।

यही वह संदर्भ है जिसमें बांकीपुर और दतिया के परिणाम केवल दो सीटों की कहानी नहीं रह जाते। वे यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या मतदाताओं की प्राथमिकताएँ बदल रही हैं, क्या गठबंधन राजनीति नए संतुलन की तलाश में है, और क्या युवाओं, रोजगार तथा शासन से जुड़े मुद्दे अब चुनावी विमर्श के केंद्र में अधिक मजबूती से लौट रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ही तय करेंगे कि यह हार केवल एक चुनावी दुर्घटना थी या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की प्रारंभिक आहट ।बांकीपुर उपचुनाव के बाद सबसे अधिक चर्चा जिस प्रश्न की हुई, वह केवल हार का कारण नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक अर्थ का था। किसी भी गठबंधन सरकार में चुनावी परिणाम केवल एक दल का मूल्यांकन नहीं करते, बल्कि सहयोगियों के बीच विश्वास, नेतृत्व की स्वीकार्यता और सामाजिक समीकरणों की मजबूती की भी परीक्षा लेते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात को राजनीतिक हलकों में सामान्य शिष्टाचार से अधिक महत्व दिया गया।

औपचारिक रूप से यह कहा गया कि बातचीत बिहार और पूर्वी भारत के विकास से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित थी। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि सरकार का काम विकास योजनाओं पर चर्चा करना ही है। लेकिन राजनीति में समय और परिस्थितियाँ अक्सर संदेश का हिस्सा बन जाती हैं। चुनावी झटके के तुरंत बाद हुई किसी भी उच्चस्तरीय बैठक को राजनीतिक संदर्भों से अलग करके देखना आसान नहीं होता। यदि सहयोगी दलों के नेताओं से चुनावी प्रतिक्रिया भी ली गई हो, तो यह किसी भी लोकतांत्रिक दल के लिए असामान्य प्रक्रिया नहीं कही जाएगी। चुनाव के बाद समीक्षा राजनीतिक दलों के संगठनात्मक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा होती है ।बिहार की राजनीति का स्वभाव हमेशा सामाजिक समीकरणों और नेतृत्व की स्वीकार्यता से गहराई से जुड़ा रहा है। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद मतदाताओं के मन में किस प्रकार की प्रतिक्रिया बनी, इसका पहला स्पष्ट संकेत इसी उपचुनाव में खोजने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव केवल विकास के प्रश्नों पर नहीं लड़े जाते; वे भावनात्मक स्वीकार्यता और राजनीतिक संदेशों से भी प्रभावित होते हैं। यदि मतदाताओं के बीच किसी प्रकार की भ्रम या असंतोष की भावना बनती है, तो उसका असर सीमित क्षेत्र में भी दिखाई दे सकता है।

इसी संदर्भ में जनता दल (यूनाइटेड) के कुछ नेताओं के सार्वजनिक वक्तव्य भी चर्चा का विषय बने। उन्होंने मतदाताओं के बीच नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बनी धारणाओं की ओर संकेत किया। लोकतंत्र में धारणाएँ कई बार वास्तविक घटनाओं जितनी ही प्रभावशाली होती हैं। राजनीति केवल निर्णयों से नहीं, बल्कि उन निर्णयों के बारे में जनता क्या सोचती है, इससे भी संचालित होती है। इसलिए किसी भी सरकार के लिए जनसंचार और राजनीतिक संवाद उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने प्रशासनिक निर्णय।

लेकिन बिहार का राजनीतिक समीकरण केवल गठबंधन तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ महीनों में युवाओं से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, रोजगार के अवसर, शिक्षा व्यवस्था और भविष्य की अनिश्चितता ने बड़ी संख्या में युवाओं को सक्रिय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया है। किसी भी लोकतंत्र में युवा असंतोष को केवल कानून-व्यवस्था के प्रश्न के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अपेक्षाओं का भी प्रतिबिंब होता है ।विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने यह संकेत दिया है कि नई पीढ़ी केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं है। वह संस्थागत पारदर्शिता, समयबद्ध प्रक्रिया और समान अवसर की अपेक्षा करती है। डिजिटल युग का युवा सूचनाओं तक तेजी से पहुँचता है, अपनी राय खुलकर व्यक्त करता है और चुनावी व्यवहार में भी अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र दिखाई देता है। यह परिवर्तन सभी राजनीतिक दलों के लिए नई चुनौती भी है और नया अवसर भी।

कुमार कृष्णन

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

डिजिटल फिल्म पाइरेसी पर सरकार का निर्णायक प्रहार

भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन उद्योग नहीं,बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मक अभिव्यक्ति और आर्थिक विकास का एक सशक्त स्तंभ है ।हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रतिवर्ष हजारों फिल्मों, वृत्तचित्रों और वेब-आधारित कंटेंट का निर्माण होता है,जिनसे लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी है ।अभिनेता, निर्देशक, लेखक, तकनीशियन,संगीतकार, वितरक, सिनेमाघर संचालक और डिजिटल प्लेटफॉर्म–सभी इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। किंतु पिछले एक दशक में इस उद्योग के सामने सबसे गंभीर चुनौती के रूप में उभरी है डिजिटल फिल्म पाइरेसी। इंटरनेट की बढ़ती पहुँच और संचार तकनीक के विस्तार ने जहाँ मनोरंजन को जनसुलभ बनाया है,वहीं फिल्मों की अवैध रिकॉर्डिंग और प्रसारण ने रचनात्मक उद्योग को अरबों रुपये का नुकसान पहुँचाया है ।इसी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारत सरकार ने कानूनी और संस्थागत दोनों स्तरों पर व्यापक सुधार किए हैं ।सरकार द्वारा लागू सिनेमैटोग्राफ (संशोधन)अधिनियम, 2023 भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है ।इस संशोधन ने पहली बार फिल्म पाइरेसी को स्पष्ट रूप से लक्षित करते हुए ऐसे प्रावधान जोड़े हैं,जिनसे डिजिटल माध्यमों पर अवैध रूप से फिल्में प्रसारित करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। संशोधित अधिनियम की धारा 7(1इ)(८) सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3) के अंतर्गत उन मध्यस्थों (क्लडीर्श्रैंश्रि) के विरुद्ध कार्रवाई करे, जिनके प्लेटफॉर्म पर फिल्मों की अवैध प्रतियां उपलब्ध कराई जा रही हों ।सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ु) के अनुसार यदि किसी डिजिटल मध्यस्थ को सरकार अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उसके मंच पर कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री उपलब्ध है,तो उसे तत्काल उस सामग्री को हटाना अथवा उसकी पहुँच निष्क्रिय करना अनिवार्य होगा। इसी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 लागू किए गए हैं। इन नियमों ने सोशल मीडिया मंचों, मैसेजिंग सेवाओं, वेबसाइटों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट और कठोर बनाया है।

कानून को व्यवहार में प्रभावी बनाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक संस्थागत तंत्र भी स्थापित किया है। अब किसी भी फिल्म का कॉपीराइट धारक अथवा निमार्ता इंटरनेट पर उपलब्ध पाइरेटेड कॉपी की शिकायत सीधे मंत्रालय को भेज सकता है ।शिकायत प्राप्त होने के बाद मंत्रालय संबंधित वेबसाइट, सोशल मीडिया मंच अथवा डिजिटल मध्यस्थ को तत्काल कंटेंट हटाने या उसकी पहुँच अवरुद्ध करने का निर्देश जारी करता है। इस प्रक्रिया को और अधिक तेज एवं प्रभावी बनाने के लिए मंत्रालय के संयुक्त सचिव (फिल्म) को अधिकृत किया गया है कि वे सीधे टेकडाउन नोटिस जारी कर सकें। इससे शिकायतों के निस्तारण में लगने वाला समय कम हुआ है और कॉपीराइट संरक्षण की प्रक्रिया अधिक सशक्त बनी है ।इस नई व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं ।सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब तक 7,393 यूआरएल (वफ्छर) को निष्क्रिय करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इनमें 1,263 वेबसाइटें तथा 4,996 टेलीग्राम चैनल शामिल हैं,जिनके माध्यम से फिल्मों की अवैध प्रतियां प्रसारित की जा रही थीं। यह संख्या बताती है कि फिल्म पाइरेसी अब केवल कुछ वेबसाइटों तक सीमित समस्या नहीं रही,बल्कि यह संगठित डिजिटल नेटवर्क का रूप ले चुकी थी ।सरकार की व्यापक कार्रवाई इस नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है ।विशेष रूप से टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पिछले कुछ वर्षों में पाइरेसी का प्रमुख माध्यम बनकर उभरे थे ।नई फिल्म रिलीज होने के कुछ ही घंटों के भीतर उसके उच्च गुणवत्ता वाले संस्करण हजारों चैनलों पर साझा कर दिए जाते थे ।इससे सिनेमाघरों की आय प्रभावित होती थी,ओटीटी प्लेटफॉर्म का व्यावसायिक मॉडल कमजोर पड़ता था और निमार्ताओं के निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। कई बार बड़े बजट की फिल्मों को शुरूआती सप्ताह में ही करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता था। नई कानूनी व्यवस्था ने ऐसे प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही स्पष्ट कर यह संदेश दिया है कि डिजिटल माध्यम कानून से ऊपर नहीं हैं ।फिल्म पाइरेसी का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं,बल्कि रचनात्मक भी होता है ।किसी फिल्म के निर्माण में वर्षों की मेहनत,शोध, लेखन, अभिनय,तकनीकी दक्षता और भारी वित्तीय निवेश शामिल होता है ।जब वही फिल्म बिना अनुमति इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है,तो सबसे पहले उस रचनात्मक श्रम का अवमूल्यन होता है ।इसका परिणाम यह होता है कि निमार्ता जोखिम लेने से बचते हैं,नए विषयों पर निवेश घटता है और गुणवत्तापूर्ण सिनेमा के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए पाइरेसी के विरुद्ध संघर्ष केवल कानून लागू करने का विषय नहीं, बल्कि सृजनशीलता और बौद्धिक संपदा के सम्मान का प्रश्न भी है ।भारत आज विश्व के सबसे बड़े फिल्म निर्माण देशों में अग्रणी है। भारतीय फिल्मों का बाजार अब केवल घरेलू दर्शकों तक सीमित नहीं रहा,बल्कि एशिया, यूरोप,अमेरिका,मध्य- पूर्व और अफ्रीका तक उसका विस्तार हो चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भारतीय फिल्मों को वैश्विक दर्शक दिए हैं। ऐसे में यदि कॉपीराइट सुरक्षा मजबूत होगी,तो विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ मजबूत होंगी और भारतीय मनोरंजन उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए सरकार के हालिया कदम को केवल कानून में संशोधन के रूप में नहीं,बल्कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने की दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए ।हालाँकि इस चुनौती का समाधान केवल सरकारी कार्रवाई से संभव नहीं है। डिजिटल नागरिकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अनेक लोग यह समझे बिना कि वे दंडनीय अपराध में भागीदार बन रहे हैं,पाइरेटेड वेबसाइटों से फिल्में डाउनलोड करते हैं, टेलीग्राम लिंक साझा करते हैं अथवा अवैध प्रतियों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करते हैं ।यह प्रवृत्ति न केवल कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है,बल्कि रचनात्मक उद्योग को आर्थिक क्षति पहुँचाने का माध्यम भी है ।इसलिए जन-जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यह समझाना आवश्यक है कि डिजिटल चोरी भी उतनी ही गंभीर है जितनी किसी भौतिक वस्तु की चोरी ।मनोरंजन उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए दर्शकों को अधिकृत सिनेमाघरों, लाइसेंस प्राप्त ओटीटी प्लेटफॉर्म और वैध डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने की आदत विकसित करनी होगी ।जब दर्शक वैध माध्यमों को अपनाएँगे,तभी कलाकारों, तकनीशियनों और निमार्ताओं के श्रम का उचित सम्मान सुनिश्चित होगा। विकसित भारत की परिकल्पना में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और डिजिटल नैतिकता का पालन समान रूप से आवश्यक है।

लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने बताया कि सरकार ऑनलाइन फिल्म पाइरेसी के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई कर रही है ।यह जानकारी सांसद बालाशौरी वल्लभनेनी द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कॉपीराइट धारकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित मध्यस्थों को शीघ्र कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सामग्री तक पहुँच तत्काल निष्क्रिय कराई जाती है।

निस्संदेह,सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी कानून का समन्वित उपयोग भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक नई सुरक्षा-व्यवस्था का निर्माण करता है ।7,393 यूआरएल,1,263 वेबसाइटों और 4,996 टेलीग्राम चैनलों के विरुद्ध की गई कार्रवाई केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि यह स्पष्ट संदेश है कि डिजिटल युग में भी कानून सर्वोपरि है ।यदि इसी दृढ़ता के साथ कानूनी कार्रवाई, तकनीकी निगरानी,जन-जागरूकता और उद्योग का सहयोग निरंतर बना रहा, तो भारत न केवल फिल्म पाइरेसी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगा,बल्कि अपनी रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी अधिक सुरक्षित,सशक्त और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकेगा।

विनोद कुमार सिंह तकियावाला

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

कट्टरता के विरुद्ध उठती आवाज और अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक - तसलीमा नसरीन

सच बोलने का साहस अक्सर सबसे महंगा पड़ता है। बांग्लादेश की प्रख्यात लेखिका तसलीमा नसरीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। वर्ष 1993 में प्रकाशित उनकी बहुचर्चित पुस्तक ₹लज्जा₹ ने धार्मिक कट्टरता, सामाजिक असहिष्णुता और विशेष रूप से मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति पर गंभीर बहस छेड़ दी थी। इसके बाद उन्हें ईशनिंदा के आरोपों, धमकियों और फतवों का सामना करना पड़ा तथा 1994 में अपना देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। तीन दशक बाद भी उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उनके प्रत्येक वक्तव्य पर आज भी तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आती हैं। हाल ही में 19 वर्षों बाद कोलकाता पहुंचीं तसलीमा नसरीन ने प्रसिद्ध रवींद्र सदन में आयोजित एक कट्टरता विरोधी साहित्यिक कार्यक्रम मेंने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि धार्मिक शिक्षा के स्थान पर रोजगारोन्मुख और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनके इस बयान का कुछ संगठनों ने कड़ा विरोध किया, जबकि अनेक बुद्धिजीवियों ने इसे विचार विमर्श का विषय बताया ।लोकतंत्र में किसी विचार से असहमति स्वाभाविक है, किंतु असहमति का उत्तर धमकी, भय या हिंसा नहीं हो सकता।

पेशे से कभी चिकित्सक रहीं तसलीमा नसरीन अपने खुले विचारों और समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध मुखर लेखन के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इस्लाम में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, धार्मिक कट्टरता तथा धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले मुल्ला-मौलवियों की आलोचना की है। मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और समान अधिकारों की वकालत करने के कारण वे न केवल बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान सहित कई देशों के कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर रहीं। लेखन के प्रति अपने समर्पण के कारण उन्होंने चिकित्सकीय पेशा छोड़कर साहित्य और समाज सेवा को अपना जीवन बना लिया। उनकी अधिकांश रचनाएँ सामाजिक यथार्थ, मानवीय पीड़ा और कुरीतियों पर आधारित हैं। तसलीमा नसरीन के पास स्वीडन की नागरिकता भी है, किंतु वे कई सालो से केंद्र भारत सरकार की विशेष अनुमति के आधार पर भारत में निवास कर रही हैं।

वर्ष 2007 में उनकी पुस्तक ₹द्विखंडित₹ को लेकर भी विवाद हुआ। पुस्तक में महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले यौन शोषण तथा धार्मिक कट्टरता पर की गई टिप्पणियों के कारण कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुए और तत्कालीन राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। सुरक्षा कारणों से उन्हें लंबे समय तक नई दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच रहना पड़ा। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है, किंतु किसी लेखक या विचारक के मत का उत्तर तर्क और संवाद से दिया जाना चाहिए, न कि कट्टरता और उग्र विरोध से। इतिहास साक्षी है कि जब जब विचारों को दबाने का प्रयास हुआ है, तब तब समाज का बौद्धिक विकास बाधित हुआ है। यह भी उतना ही सत्य है कि किसी भी धर्म, समुदाय या शिक्षा व्यवस्था की आलोचना तथ्यों, संतुलन और संवेदनशीलता के साथ होनी चाहिए। यदि किसी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है तो उस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। सुधार का मार्ग संवाद से निकलता है, टकराव से नहीं। किसी भी समुदाय के अधिकांश लोग शांति, शिक्षा और प्रगति के पक्षधर होते हैं; इसलिए कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं के आधार पर पूरे समुदाय का आकलन उचित नहीं माना जा सकता। तसलीमा नसरीन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक लेखक की कलम सत्ता, कट्टरता और सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दे सकती है। उन्होंने महिलाओं की समानता, शिक्षा और स्वतंत्रता के पक्ष में लगातार आवाज उठाई है। उनके विचारों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार लोकतांत्रिक मूल्यों का अभिन्न अंग है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज में कट्टरता के स्थान पर सहिष्णुता, संवाद और विवेक को बढ़ावा दिया जाए। विचारों का मुकाबला विचारों से ही होना चाहिए। किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसकी असहमति को सुनने और उसका उत्तर तर्क से देने की क्षमता से होती है। यदि हम वास्तव में प्रगतिशील और लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के प्रयासों का सम्मान करना होगा। यही लोकतंत्र की आत्मा है और यही एक सभ्य समाज की सबसे बड़ी शक्ति भी।

अरविन्द रावल

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त समाचार

उत्तर कोरिया ने अमेरिका के नेतृत्व में युद्धाभ्यास को बताया आक्रामक युद्ध की रिहर्सल

सोल। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के नेतृत्व में हाल ही में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक को आक्रामक युद्ध की रिहर्सल करार दिया है। साथ ही उसने चेतावनी दी कि वह इसके जवाब में प्रतिरोधक क्षमता को नए स्तर पर ले जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को एक सैन्य टिप्पणीकार के हवाले से प्रकाशित लेख में कहा गया है कि रिमपैक अभ्यास दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का प्रतीक है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में सैन्य दबदबा कायम करना है। लेख में दावा किया गया कि इस बार अभ्यास में दक्षिण कोरिया और जापान की भूमिका पहले की तुलना में ज्यादा व्यापक रही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वाशिंगटन तीनों देशों के बीच सैन्य समन्वय और संयुक्त अभियान क्षमता को और मजबूत करना चाहता है। अमेरिकी प्रशांत बेड़े के उप-कमांडर के उस बयान का भी इसमें उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया था कि दक्षिण कोरिया और जापान की भूमिका केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक सैन्य अभियानों के लिए अहम है। उत्तर कोरिया ने इसे इस बात का प्रमाण बताया कि दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यासों में शामिल रिमपैक का उद्देश्य संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी करना है। उत्तर कोरिया ने हाल के दक्षिण कोरिया-अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रोग्राम्स की भी आलोचना की। प्योंगयांग का आरोप है कि ये गतिविधियां कोरियाई प्रायद्वीप में संभावित सैन्य संघर्ष की तैयारी का हिस्सा हैं। लेख में कहा गया कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया का त्रिपक्षीय सैन्य सहयोग अब रेड लाइन पार कर चुका है और यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा के लिए नया संकट पैदा कर रहा है। उत्तर कोरिया ने दोहराया कि वह किसी भी बढ़ते सैन्य खतरे का जवाब अपनी प्रतिरोधक क्षमता को उसी स्तर तक बढ़ाकर देगा। देश की सुरक्षा नीति का मूल सिद्धांत यही है कि नई स्तर के खतरे का मुकाबला नई स्तर की प्रतिरोधक क्षमता से किया जाएगा।

नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर इस्तीफे के अंतरराष्ट्रीय दबाव को सरकार ने बताया 'काल्पनिक'

काठमांडू। नेपाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर इस्तीफा देने का दबाव बनाए जाने संबंधी तीन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के संयुक्त बयान को पूरी तरह काल्पनिक और निराधार करार दिया है। प्रतिनिधि सभा की कानून, न्याय एवं संसदीय समिति की बैठक में उठे सवालों का जवाब देते हुए बुधवार को कानून मंत्री सोबिता गौतम ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स (आईसीजे) और ह्यूमन राइट्स वॉच के संयुक्त बयान में लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है। इन तीनों संस्थाओं ने अपने संयुक्त बयान में दावा किया था कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया है और इस्तीफा नहीं देने पर उनके खिलाफ महाभियोग लाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही बयान में यह भी कहा गया था कि वरिष्ठता की अनदेखी करके प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश उचित नहीं था तथा प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत पर संसदीय सुनवाई समिति में सार्थक चर्चा नहीं हुई। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री गौतम ने कहा, "यह पूरी तरह काल्पनिक है।" उन्होंने कहा कि यह मामला नेपाल की संप्रभुता में हस्तक्षेप का प्रयास है और इस विषय पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। मंत्री गौतम ने यह भी आरोप लगाया कि इस बयान में राजनीतिक पूर्वाग्रह झलकता है। उन्होंने कहा, "इसमें राजनीतिक गंध दिखाई देती है।" संयुक्त बयान में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल और कुमार रेग्मी का नाम लेते हुए दावा किया गया था कि उन पर इस्तीफा देने का दबाव डाला गया और ऐसा न करने पर महाभियोग की चेतावनी दी गई। कानून मंत्री ने कहा कि इन गंभीर आरोपों के समर्थन में संबंधित संस्थाओं को ठोस आधार और प्रमाण सार्वजनिक करने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद में किसी भी विषय पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, लेकिन बिना किसी साक्ष्य के बाहरी संस्थाओं द्वारा नेपाल के आंतरिक मामलों पर अनावश्यक टिप्पणी करना उचित नहीं है।

राष्ट्रचिंतक रामबहादुर राय को दिया जाएगा 'पद्मभूषण युगतुलसी प. रामकिंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार'

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के तुलसी शोध संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं राष्ट्रचिंतक रामबहादुर राय को वर्ष-2026 के लिए 'पद्मभूषण युगतुलसी पं. रामकिंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को मप्र जनजातीय संग्रहालय के निदेशक सुदेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि कि अलंकरण समारोह का आयोजन भोपाल के तुलसी मानस प्रतिष्ठान (मानस भवन) में गुरुवार, 06 अगस्त को 04 बजे किया जा रहा है। समारोह में राष्ट्रचिंतक रामबहादुर राय को उक्त पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एक जुलाई, 1946 को गाजीपुर (उप्र) में जन्मे रामबहादुर राय हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं चिंतक हैं। वे वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के अध्यक्ष हैं। साथ ही वे देश की सबसे पुरानी बहुभाषी समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के समूह संपादक हैं। समाज, राजनीति और समसामयिक विषयों पर उनके लेखन एवं संपादन को व्यापक सम्मान प्राप्त है। रामबहादुर राय ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बिहार आन्दोलन में हिस्सेदारी और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 1971 में रिपोर्टिंग की। वे जे.बी. कृपलानी मेमोरियल ट्रस्ट में ट्रस्टी रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न योगदान-संवाददाता- जनसत्ता (1983), मुख्य संवाददाता-जनसत्ता (1984-86), विशेष संवाददाता-नवभारत टाइम्स (1986-91), ब्यूरो चीफ जनसत्ता (1991-96), सम्पादक जनसत्ता समाचार सेवा (1996-2004)। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में सतत् सक्रिय लेखन।

तेलंगाना में शुरू हुई एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन 112, एक कॉल पर मिलेंगी 18 सेवाएं

हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने राज्यभर में नागरिकों के लिए एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) लागू करते हुए 112 को एकल आपातकालीन हेल्पलाइन के रूप में शुरू कर दिया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सी.वी. आनंद ने बुधवार को बंजारा हिल्स स्थित तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (टीजीआईसीसीसी) में इस सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया। डीजीपी सी.वी. आनंद ने बताया कि डायल 112 के माध्यम से नागरिकों को एक ही फोन कॉल पर 18 आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच मिलेगी। इनमें पुलिस, अग्निशमन (फायर) और चिकित्सा आपातकालीन सेवाएं प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित, प्रभावी और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को अलग-अलग हेल्पलाइन नंबरों की बजाय एक ही नंबर पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकें। नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवाओं के लिए नागरिक सीधे 112 पर कॉल कर तत्काल सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही पुलिस सहायता के लिए पहले इस्तेमाल होने वाला डायल 100 अब 112 प्रणाली में समाहित कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस एकीकृत हेल्पलाइन को विभिन्न आपातकालीन एजेंसियों के बीच तेज समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। 112 पर कॉल प्राप्त होने के बाद प्रणाली आपात स्थिति का आकलन कर संबंधित विभाग को तत्काल अलर्ट भेजेगी, जिससे राहत और बचाव कार्य में तेजी आएगी। यह पहल तेलंगाना को राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) से भी जोड़ती है, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख आपातकालीन सेवाओं के लिए एकल संपर्क बिंदु उपलब्ध कराना है। सरकार को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से आपातकालीन सेवाओं की प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और मजबूत होगा तथा आम नागरिकों को अधिक प्रभावी और सुलभ सहायता मिल सकेगी। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि 112 हेल्पलाइन का उपयोग केवल वास्तविक आपात स्थितियों में ही करें, ताकि संसाधनों का उचित उपयोग हो और जरूरतमंद लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सके।

ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से भोपाल में

एजेंसी, भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में चार दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन-2026 शुरू होगा। इसका समापन आठ अगस्त को होगा। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में आयोजित इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और भागीदार 10 देशों के संस्कृतिमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण और आपसी साझेदारी से जुड़े कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि 5 और 6 अगस्त को अधिकारी स्तर पर नीतिगत प्रारूपों और विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। 7 और 8 अगस्त को संस्कृति मंत्रियों एवं उपमंत्रियों के स्तर पर विचार-विमर्श कर अंतिम सहमति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व प्रथम चरण में सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक में शुरुआती प्रारूप पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद वाराणसी में आयोजित दूसरी बैठक में प्रतिनिधियों ने गहन मंथन किया । अब भोपाल में आयोजित तीसरी और अंतिम बैठक घोषणा-पत्र पर सभी देशों की औपचारिक मुहर लगाएगी।

अग्रवाल ने बताया कि आज शाम प्रतिनिधि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दौरा करेंगे, जहां पॉटरी (मृदा शिल्प) प्रदर्शनी में उनका पारंपरिक स्वागत किया जाएगा और स्वदेशी शिल्प व पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के लाइव प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। इसके बाद प्रतिनिधि ट्राइबल हैबिटेट में 'नागा हाउस' और 'हिमालयी गांव' का गाइडेड भ्रमण कर वहां की वास्तुकला, जीवन शैली व सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात वीथि संकुल में औपचारिक दीप प्रज्वलन ('अल्वीलाक्कू') व दीर्घाओं के भ्रमण के बाद प्रेक्षागृह में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कथक नृत्य, पारंपरिक सामुदायिक नृत्य और भारत की विविध पारंपरिक व जनजातीय पोशाकों को प्रदर्शित करने वाला एक फैशन शो प्रस्तुत किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्यसमूह की बैठक में 6 अगस्त को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों के घोषणापत्र के मसौदे और सांस्कृतिक सहयोग के अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इनमें सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, संग्रहालय, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और ब्रिक्स देशों के बीच लोगों से लोगों का जुड़ाव शामिल है। कार्य समूह की सिफारिशें मंत्रस्तरीय बैठक के दौरान संस्कृति मंत्रियों के विचार का आधार बनेंगी। शाम को रवींद्र भवन भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। यह कार्यक्रम आम जनता के लिए खुला रहेगा और भाग लेने वाले देशों की समृद्ध और विविध प्रदर्शन कला परंपराओं को देखने का अवसर प्रदान करेगा।

कई पूर्व नौकरशाह, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल

एजेंसी, नई दिल्ली

कांग्रेस के मुख्यालय में बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान कई पूर्व नौकरशाह, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान इंडियन पब्लिक जस्टिस पार्टी और समाज विकास क्रांति पार्टी के कांग्रेस में विलय की भी घोषणा की गयी। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले प्रमुख लोगों में बसपा के पूर्व नेता डॉ. अनूप कुमार अंबेडकर, अधिवक्ता मयंक यादव, अधिवक्ता श्रेय यादव, उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी सुनील कुमार वर्मा, पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस चौधरी खुशीराम, उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त आईपीएस बीपी अशोक, केरल के पूर्व डीजीपी सुदेश कुमार, किसान नेता रोहित जाखड़, सेवानिवृत्त नौकरशाह विक्रांत गौतम, सचिन कुमार, किशन स्वरूप, आरके मैसी, राजेंद्र प्रसाद विशप, अमित कुमार, राष्ट्रीय लोक दल की पूर्व सचिव सावित्री गौतम, अरुण बंसवाल और अशोक सिंह शामिल हैं।कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अनिल जैयहिंद तथा सांसद राकेश राठौर की मौजूदगी में सभी नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली।इस दौरान बीपी अशोक ने अपनी इंडियन पब्लिक जस्टिस पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, जबकि अशोक सिंह ने समाज विकास क्रांति पार्टी का कांग्रेस में विलय करने की घोषणा की।कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने शिक्षा महंगी की, सार्वजनिक उपक्रम बेचे, देश पर कर्ज बढ़ाया और सरकारी स्कूल बंद किए।कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अनिल जैयहिंद ने कहा कि एक ओर राजनीतिक दल टूट रहे हैं और सांसद दल बदल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनता का समर्थन कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं में भारी असंतोष है और प्रयागराज में होने वाला 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम गेम चेंजर साबित होगा।

चिट फंड मामले में वाईएसआरसीपी नेता के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

एजेंसी, हैदराबाद

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कथित बहु-राज्यीय चिट फंड घोटाले से जुड़े धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के नेता मल्ला विजय प्रसाद से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीमों ने विशाखापत्तनम और हैदराबाद में पांच स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान पूर्व विधायक एवं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मल्ला विजय प्रसाद के आवास, कार्यालय और अन्य परिसरों में चलाया गया। बताया गया कि कार्रवाई में ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ईडी टीमों ने भी भाग लिया। छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था। ईडी मल्ला विजय प्रसाद और वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ कथित चिट फंड घोटाले और उससे जुड़े धनशोधन के आरोपों की जांच कर रही है। आरोप है कि कंपनी के माध्यम से विभिन्न राज्यों के निवेशकों से धन जुटाकर वित्तीय अनियमितताएं की गईं। मल्ला विजय प्रसाद वर्तमान में विशाखापत्तनम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से वाईएसआरसीपी के समन्वयक हैं। उनके खिलाफ पहले भी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में विभिन्न मामले दर्ज हो चुके हैं। 2021 में ओडिशा पुलिस ने 2019 के एक कथित चिट फंड मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। उस समय वह आंध्र प्रदेश एजुकेशन एंड वेलफेयर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे। 1,200 करोड़ रुपये के कथित चिट फंड घोटाले में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के हजारों जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी किए जाने के आरोप हैं।

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे धंसने के मामले में एनएचएआई ने की कार्रवाई, पीएनसी इंफ्राटेक पर शिकंजा

एजेंसी, नई दिल्ली

नई दिल्ली। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने निर्माण कंपनी, स्वतंत्र इंजीनियर और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। एनएचएआई ने निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को 'नॉन-परफॉर्मर' घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही एक्सप्रेसवे पर फिलहाल टोल वसूली भी रोक दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 26 जुलाई को किलोमीटर 64 के पास करीब 300 मीटर हिस्से में सड़क धंसने (स्लिपेज) की घटना सामने आई थी। इसके बाद एनएचएआई ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कराया और प्रभावित हिस्से की व्यापक तकनीकी जांच के आदेश दिए।

एनएचएआई ने पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उसके खिलाफ प्रदर्शन सुरक्षा राशि का दो प्रतिशत जुर्माना लगाने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तीन वर्ष तक डिबारमेंट की कार्रवाई करने तथा कंपनी की रेटिंग घटाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही कंपनी को अपने खर्च पर करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से प्रभावित हिस्से की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर एनएचएआई का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

प्राधिकरण ने परियोजना में लापरवाही बरतने के आरोप में निर्माण एजेंसी के परियोजना प्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता, स्वतंत्र इंजीनियर के टीम लीडर सुरेंद्र कुमार और रेजिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार को परियोजना से हटाकर दो वर्षों के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल की परियोजनाओं से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा वर्तमान परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा को उनके मूल विभाग भेज दिया गया है। वहीं, पूर्व परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया और वर्तमान परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा के खिलाफ कथित लापरवाही को लेकर आरोप पत्र जारी किए जा रहे हैं।

एनएचएआई ने परियोजना के स्वतंत्र इंजीनियर एम/एस थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी भविष्य की परियोजनाओं से डिबार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे की पूरी सड़क की स्थिति का आकलन करने के लिए लेजर प्रोफिलोमीटर तकनीक से जांच कराने का निर्णय लिया है। साथ ही आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर केएस रेड्डी के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम को तकनीकी जांच सौंपी गई है, जो घटना के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। एनएचएआई ने कहा कि प्रभावित हिस्से की पूरी तरह मरम्मत होने तक एक्सप्रेसवे पर किसी भी वाहन से टोल नहीं लिया जाएगा। टोल बंद रहने से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई भी निर्माण कंपनी से ही की जाएगी।

वाराणसी में गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर में सीधे हाई स्पीड से विश्वनाथ तक पहुंच सकेंगे वाहन

एजेंसी, नई दिल्ली

वाराणसी में 14,447.64 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 46.039 किलोमीटर लंबे छह लेन के ग्रीनफील्ड गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर से राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (एनएच-19) से वाराणसी रिंग रोड तक तेज वाहनों का निर्बाध संचालन होगा। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट, बीएचयू, रामनगर और काशी रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थलों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। इस कॉरिडोर पर वाहन 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे, जिससे शहर में औसत यात्रा समय 60 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को परियोजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने इस कॉरिडोर को मंजूरी दी थी। परियोजना का उद्देश्य वाराणसी और चंदौली में बढ़ते यातायात दबाव को कम करना, तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाना और शहर को आधुनिक परिवहन सुविधाओं से जोड़ना है। मंत्रालय के अनुसार, यह एक्सेस कंट्रोल छह लेन एलिवेटेड कॉरिडोर एनएच-19, वाराणसी रिंग रोड (एनएच-135बी), रामनगर और बीएचयू को आपस में जोड़ेगा। कॉरिडोर पर वाहनों की परिचालन गति 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके बनने से परियोजना क्षेत्र में औसत यात्रा समय करीब 60 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगा, जबकि एनएच-19 से काशी रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 50 मिनट से घटकर 25 मिनट हो जाएगा।

परियोजना में गंगा नदी पर 910 मीटर लंबा केबल-स्टे पुल बनाया जाएगा। इसके अलावा 1.32 किलोमीटर लंबा एक्स्ट्राडोज्ड फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जिसमें ट्रैवलेटर की सुविधा होगी। इससे पैदल यात्रियों को काशी विश्वनाथ मंदिर तक सुरक्षित और आसान पहुंच मिलेगी। परियोजना में मौजूदा और प्रस्तावित मालवीय पुल के ऊपर रेल ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा। यातायात सुचारु रखने के लिए बीएचयू-लंका से सामने घाट तक एलिवेटेड स्पर तैयार किया जाएगा, जिससे लंका चौराहे पर जाम की समस्या कम होगी। परियोजना में आपातकालीन पार्किंग बे, शोर कम करने के लिए नॉइज बैरियर, आकर्षक फसाड लाइटिंग तथा वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित वास्तुशिल्पीय डिजाइन भी शामिल किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, यह कॉरिडोर प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बहु-माध्यम (मल्टीमॉडल) संपर्क को भी मजबूत करेगा। इससे एनएच-19, वाराणसी रिंग रोड, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, काशी रेलवे स्टेशन और रामनगर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। इससे यात्रियों के साथ-साथ माल परिवहन भी अधिक तेज और सुगम होगा। मंत्रालय ने कहा कि बेहतर संपर्क और कम यात्रा समय से वाराणसी आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।

केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर लगाया विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप

एजेंसी, नई दिल्ली

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने संसद में जारी गतिरोध के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार जनता और विपक्ष की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा है, लेकिन सरकार किसी भी विषय पर चर्चा नहीं कराना चाहती।

संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष देश की जनता की आवाज को संसद में उठा रहा है, लेकिन सरकार उसे सुनने के बजाय उससे बच रही है। गृहमंत्री संसद में आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। संसद में जारी गतिरोध का समाधान सरकार को ही निकालना होगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की। बिहार में छात्रों पर एके 47 चलाई गई। इन घटनाओं पर गृहमंत्री को संसद में जवाब देना चाहिए। विपक्ष केवल इन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है।

वेणुगोपाल ने राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी पर कहा कि इस मामले में जवाबदेही तय नहीं की गई है और न ही निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। विपक्ष यह जानना चाहता है कि राम मंदिर के चढ़ावे के मामले में क्या हुआ, लेकिन सरकार इस पर चर्चा से बच रही है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संसद में ई-20 से जुड़े मुद्दे और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का विषय भी उठाया है। ये सभी जनहित के मुद्दे हैं, लेकिन सरकार इनमें से किसी पर भी चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश से मिली गर्मी से राहत, कई इलाकों में जलभराव

एजेंसी, चेन्नई

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह से रुक-रुक कर हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई। साथ ही कई क्षेत्रों में जलभराव के कारण यातायात प्रभावित रहा और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। महरौली-बदरपुर रोड, दक्षिणपुरी सहित कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं तथा मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजधानी दिल्ली में बुधवार को अब तक करावल नगर, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, बुद्धा जयंती पार्क, दिल्ली कैंट, इंडिया गेट, सफदरजंग, लोदी रोड, नेहरू स्टेडियम, आरके पुरम, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, हौज खास, मालवीय नगर, कालकाजी और तुगलकाबाद सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है।

मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे के बीच सर्वाधिक 49.3 मिमी वर्षा अयानगर में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा छतरपुर में 24 मिमी, सफदरजंग में 15.4 मिमी, पालम में 8.3 मिमी, लोधी रोड में 3.9 मिमी तथा रिज क्षेत्र में 3 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बारिश के चलते पूरे एनसीआर में मौसम सुहावना हो गया है। राजधानी के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम रहा।

तमिलनाडु बजट 2026-27: शिक्षा, महिलाओं, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर सरकार का फोकस

एजेंसी, चेन्नई

♦ **वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य की कुल आय 3,50,027 करोड़, राजस्व घाटा 55,775 करोड़, जबकि राज्य पर कुल कर्ज 10,98,765 करोड़ रुपये होने का अनुमान**

तमिलगा वेत्रि कड़गम (टीवीके) सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे मंत्री मरिया विल्सन ने सुबह 10 बजे बजट भाषण शुरू किया, जो दोपहर 12:33 बजे तक चला। करीब दो घंटे 33 मिनट के अपने पहले बजट भाषण में उन्होंने शिक्षा, महिला कल्याण, रोजगार, आधारभूत संरचना, पर्यटन, कृषि, सामाजिक न्याय और सुशासन को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं बताया। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य की कुल आय 3,50,027 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजस्व घाटा 55,775 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि राज्य पर कुल कर्ज 10,98,765 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति को पूरी तरह पटरी पर लाने में कम से कम दो वर्ष का समय लगेगा।

बजट में महिला कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। सरकार ने सभी महिलाओं को परिवार का सदस्य मानते हुए उन्हें आठ ग्राम का स्वर्ण सिक्का और रेशमी साड़ी उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की, जिसके लिए 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 'सिंगप्पेण सशक्तिकरण योजना' शुरू करने और महिला स्वयं सहायता समूहों को इस वर्ष 38 हजार करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 44,527 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 'वेत्री मणिक्कणिनी योजना' पर 8,393 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए दो हजार करोड़ रुपये की लागत से विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। राज्य के 10 हजार सरकारी विद्यालयों में 'सुपर क्लीन, सुपर कैंपस' योजना लागू होगी। बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और पोषण के लिए 500 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

तमिलनाडु की सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को बढ़ावा देने के लिए विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा की। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों के पांच लाख युवाओं को एआई कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

06-08-2026 T.P. Page 8_Layout 1 06-08-2026 09:30 Page 1

विजय वर्मा ने स्ट्रगल के दिनों को किया याद

एक्टर विजय वर्मा आज अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। 'गली बॉय', 'दहाड़' और 'डार्लिंग्स' जैसी फिल्मों और सीरीज में उन्होंने शानदार काम किया है। लेकिन बॉलीवुड तक उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। विजय वर्मा ने प्रखर गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, 'मैंने हैदराबाद में थोड़ी-बहुत मॉडलिंग करने की कोशिश की थी, छोटे लेवल पर। लेकिन वहां एक अजीब मॉडल कोऑर्डिनेटर मिला। वो मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा, जैसे मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उससे कहा, 'भाई ये क्या कर रहे हो?'' उन्होंने आगे बताया कि इस अनुभव से वह काफी निराश हो गए थे। विजय ने आगे कहा, 'जब आप नए होते हैं, तो जल्दी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे एक्टिंग ही करनी है, तो मुझे डटकर सामना करना होगा।'

उन्होंने बताया, 'मैं हैदराबाद के सूत्रदार स्कूल ऑफ एक्टिंग गया और कहा कि मुझे एक्टिंग सीखनी है। लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कमिटमेंट और मेहनत चाहिए, ये दो दिन का काम नहीं है। मुझे लगा कि वो मुझे मौका ही नहीं दे रहे।' इसके बाद विजय ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अप्लाई किया, लेकिन वहां भी पहली बार में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरी बार कोशिश करने पर उन्हें एडमिशन मिल गया। वहां उन्होंने राजकुमार राव और जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स के साथ पढ़ाई की।

विजय वर्मा का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो विजय वर्मा हाल ही में विभु पुरी की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में नजर आए थे। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, फातिमा सना शेख और शारिब हाशमी भी थे। यह फिल्म फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म थी। इसके अलावा विजय हाल ही में वेब सीरीज 'मटका किंग' में भी दिखे, जिसमें एक साधारण कॉटन व्यापारी के गैम्बलिंग डॉन बनने की कहानी दिखाई गई है।

साई पल्लवी की सादगी की मुरीद हैं निहारिका एनएम

तब्बू और श्रीदेवी को भी बताया अपनी प्रेरणा

सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया से फिल्मों तक का सफर तय करने वाली अभिनेत्री निहारिका एनएम ने अभिनेत्री साई पल्लवी को अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस बताया। उन्होंने कहा कि साई पल्लवी की सादगी, शानदार अभिनय और व्यक्तित्व उन्हें हमेशा प्रेरित करता है। खास बातचीत में निहारिका एनएम ने कहा, ''साई पल्लवी उन अभिनेत्रियों में से हैं, जिन्हें मैं लंबे समय से पसंद करती हूं। उनकी सादगी, खूबसूरती और अपने काम के प्रति समर्पण उन्हें सबसे अलग बनाता है। वह मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं।'' निहारिका ने कहा, 'साई पल्लवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने बिना किसी बनावटी छवि के दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है और यही बात मुझे बेहद पसंद आती है। मेरा मानना है कि आज के समय में ऐसे कलाकार बहुत कम हैं जो अपनी सादगी और स्वाभाविक अंदाज से लोगों का दिल जीतते हैं।'

साई पल्लवी के अलावा निहारिका ने बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने तब्बू को सदाबहार कलाकार बताते हुए कहा, ''वह आज भी अपनी अभिनय क्षमता से हर किरदार में जान डाल देती हैं। उनकी एक्टिंग और डांस दोनों ही शानदार हैं और वह हर पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा हैं। श्रीदेवी भी भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रहीं।'' बातचीत के दौरान निहारिका ने अपनी नई फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, ''इस फिल्म से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण इसकी कहानी थी। जब मैंने पहली बार फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे यह काफी मजेदार लगी। मैंने महसूस किया कि यह ऐसी फिल्म है, जिसे मैं खुद भी एक दर्शक के रूप में देखना पसंद करूंगी। इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए हां कह दी।'' फिल्म में अभिनेता और डांसर राघव जुयाल के साथ काम करने के अनुभव को याद करते हुए निहारिका ने कहा, ''राघव के साथ काम करना ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन दोनों ही जगह बहुत मजेदार रहा। जो सीन पर्दे पर दो-तीन सेकेंड का दिखाई देता है, उसे शूट करने में कई घंटे लग जाते हैं। ऐसे में उनकी एनर्जी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है।'' विवेक बी. अग्रवाल के निर्देशन में बनी 'भाई तेरा स्टार है' में राघव जुयाल, संजय कपूर, बरखा सिंह, चंदन रॉय सान्याल, विवान भटेना और विकल्प मेहता जैसे कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

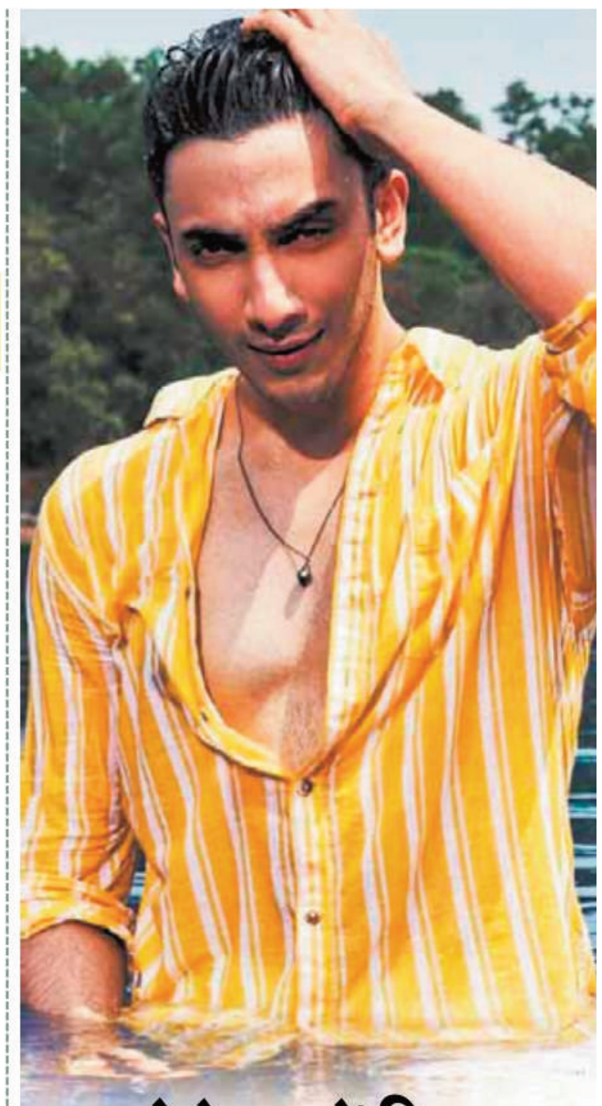

नए प्रोजेक्ट में फिर एक साथ नजर आने वाले हैं शरवरी वाघ और वेदांग रैना

फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में दर्शकों की दिल जीतने के बाद शरवरी वाघ और वेदांग रैना एक बार फिर एक नए प्रोजेक्ट में एक-साथ नजर आने वाले हैं। खबरों की मानें तो इन कलाकार को निर्देशक इम्तियाज अली की अगली रोमांटिक फिल्म में लीड रोल के लिए साइन किया गया है। इसकी शूटिंग नवंबर में शुरू हो सकती है। लंबे समय तक चली राइटिंग प्रोसेस के बाद बिना नाम वाली फिल्म की पटकथा पूरी हो गई है। इसका मुख्य डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है। कास्टिंग भी पूरी हो गई है और अब प्रोडक्शन टीम

लोकेशन खोजने, शेड्यूल बनाने और दूसरी योजना पर ध्यान देगी। ताकि इस साल के आखिर में शूटिंग शुरू हो सके। प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मेकर्स को भरोसा है कि सब कुछ सही चल रहा है। टीम अब प्री-प्रोडक्शन के आखिरी स्टेज में है और यह पक्का कर रही है कि नवंबर में प्रोडक्शन शुरू होने से पहले सभी क्रिएटिव और टेक्निकल इंतजाम पूरे हो जाएं।

लीड जोड़ी की वापसी

इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इम्तियाज अली को लगता है कि शरवरी और वेदांग रैना फिल्म के इमोशनल माहौल के लिए एकदम सही हैं। दोनों एक्टर्स ने हाल के कुछ परफॉर्मेंस से अपनी अच्छी पहचान बनाई है। उनका साथ आना इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबियों में से एक होगा।

किरदारों को चुनने में हमेशा सतर्क रहूंगी

चर्चित टीवी शो 'बालिका वधू' में आनंदी के तौर पर लोगों का दिल जीतने से लेकर मुश्किल रियलिटी शो और फिल्मों में काम करने तक, अदाकारा अविका गोर ने दर्शकों का खूब दिल जीता। उनका कहना है कि अब वे अपनी दमदार परफॉर्मेंस के जरिए पहचान पाना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि उन्हें शानदार भूमिकाओं के लिए दर्शक याद रखें। यही वजह है कि वे किरदारों का चयन भी काफी सोच-समझकर कर रही हैं।

पहले से ज्यादा जागरुक हो गई हैं अविका

बातचीत में अविका ने कहा कि वे सिर्फ ऐसे रोल नहीं करना चाहतीं, जिनमें किसी ऑब्जेक्ट की तरह दिखें। अविका स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आ रही हैं, जो आज 01 अगस्त से शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि वे ऐसी स्क्रिप्ट चुनने को लेकर ज्यादा जागरूक और सतर्क हो गई हैं, जिनमें दमदार परफॉर्मेंस का मौका मिले।

उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ यह मानती हूं कि लोग मुझसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। कुछ ऐसे किरदार हैं, जो मैं अपनी फिल्मों में करती रहती हूं, जहां मुझे अभिनय करने का मौका मिलता है। मुझे यह दिखाने का मौका मिलता है कि मैं एक कलाकार के रूप में क्या करने में सक्षम हूं। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा ध्यान हमेशा सही स्क्रिप्ट चुनने, सही किरदार चुनने पर होता है, जहां मुझे फिल्म में फर्नीचर बनने से ज्यादा कुछ करने का मौका मिलता है। यही वजह है कि मैं हमेशा सही स्क्रिप्ट चुनने और सही किरदार चुनने को लेकर बेहद सचेत रहूंगी'।

दर्शकों और फैंस को कहा शुक्रिया

टीवी शो 'बालिका वधू' में आनंदी के किरदार से मशहूर हुई अविका ने कहा कि लगभग दो दशक बाद भी शो की लगातार लोकप्रियता के लिए वे शुक्रगुजार महसूस करती हैं।

रागिनी 3 में नजर आएंगी आरजे महवश

महवश इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'रागिनी 3' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म का उन्होंने आधिकारिक एलान कर दिया है। महवश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुशी जाहिर की है। साथ ही एकता कपूर का आभार जताया है। महवश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने फिल्म 'रागिनी 3' का एलान करते हुए कुछ फोटोज शेयर की हैं, जो सेट की हैं। फिल्म को लेकर तैयारी चल रही हैं। एक तस्वीर में महवश ने हाथों में क्लैपरबोर्ड थाम रखा है, जिस पर लिखा है, 'रागिनी 3'। महवश ने लिखा है, 'अपनी अगली फिल्म 'रागिनी 3' का एलान करते हुए मैं बहुत उत्साहित हूं। जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मुझे यह मौका देने के लिए एकता कपूर मैम, बालाजी मोशन पिक्चर्स, श्रुति महाजन और हमारे निर्देशक शशांक घोष सर की हमेशा आभारी रहूंगी। बाकी तुम लोग अपने प्यार से संभाल लेना दोस्तों'।

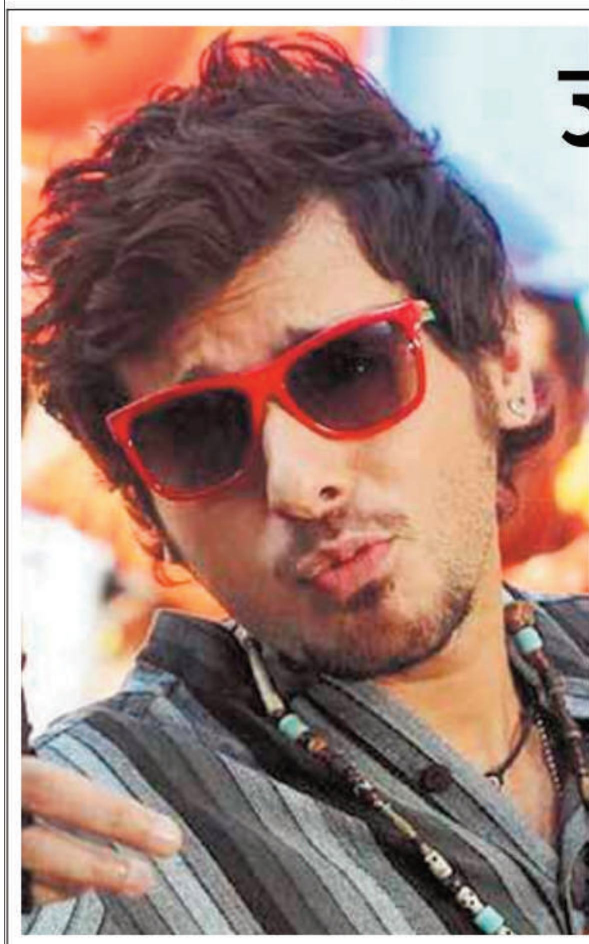

जब मैंने शुरुआत की थी तब हमारी इंडस्ट्री काफी डिसआर्गेनाइज्ड थी

दिव्येंदु बॉलीवुड के उन कलाकारों में से हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के, एक नॉन फिल्मी परिवार से आते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। हालांकि, उनका यह सफर आसान भी नहीं रहा है। फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम बनाने के लिए कैसे-कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। फिर चाहे आप भले ही कितने टैलंटेड हैं। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखकर आए दिव्येंदु को भी रिजेक्शन के लंबे दौर से गुजरना पड़ा। यही नहीं, साल 2011 में 'प्यार का पंचनामा' से वाहवाही बटोरने के बावजूद अपने अपने हिस्से की लाइमलाइट के लिए 2018 का इंतजार करना पड़ा, जब 'मिर्जापुर' आई। बीते दिनों वेब सीरीज 'ग्लोरी' और फिल्म 'पेद्दी' में तारीफ पाने के बाद अब वह आगे 'मिर्जापुर : द मूवी' में फिर से मुन्ना भैया बनकर आ रहे हैं।

पिछले दिनों आई सीरीज 'ग्लोरी' में देव के किरदार के लिए सराहे गए दिव्येंदु बताते हैं, 'जब मैंने शुरुआत की थी, तब हमारी इंडस्ट्री काफी डिसआर्गेनाइज्ड थी। तब एक ही पैटर्न पर फिल्में बनती थीं। कुछ जब हिट हो जाता था तो वैसी ही कहानियां और बनने लगती थीं। कास्टिंग जैसा प्रॉसेस तब बिल्कुल नहीं था। आज जैसे कास्टिंग डायरेक्टर तब होते नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल होती थी कि जाएं तो जाएं कहां।'

कोविड महामारी से एक अच्छी चीज हुई

दिव्येंदु कहते हैं, 'कोई गॉडफादर नहीं हैं इंडस्ट्री में, किसी से जान पहचान नहीं है। मैं थिएटर और फिल्म स्कूल से एक्टिंग सीखकर आया था। कई बार जब ऑडिशन में बताया जाता था कि सीन को ऐसे ही करना है तो कई मौकों पर ये लड़ाई होती थी कि जब तुम ही बताओगे कि सीन कैसे करना है, तो मेरा टैलंट कहां है? सच कहूं तो कोविड महामारी वैसे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, पर जैसे सागर मंथन से कुछ अच्छी, कुछ बुरी चीजें भी निकलती है। उसमें अच्छी चीज ये हुई कि लोगों ने अलग-अलग तरह की चीजें देखनी शुरू की।'

शुरआत में रास्ता खोजना बहुत मुश्किल था दर्शकों के बदले रुझान पर बात करते हुए वह कहते हैं, 'कोविड से पहले, एक सेट थाली मिलती थी कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, यही फिल्म है। एक गाना होगा, ये इमोशन सीन है, ये बदला होगा, लेकिन महामारी के दौरान लोगों ने दुनिया भर का सिनेमा देखा, जिससे यहां भी अलग-अलग तरह की चीजें भी बनने लगीं। उसका बहुत फायदा मिला। मेरे करियर के शुरुआती दौर में ये चीजें नहीं थीं, तो रास्ता खोजना बहुत मुश्किल था।'

गुस्सा आता था, लड़ता भी था

दिव्येंदु आगे बताते हैं उनके संघर्ष का दौर खासा निराशाजनक था। बकौल दिव्येंदु, 'ऑडिशन में ज्ञान देने वालों पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरी बहुत लड़ाइयां भी होती थीं और मैं कई जगह से ब्लैकलिस्टेड भी था। तब खुद पर विश्वास बनाए रखने के लिए मैं मिर्जा गालिब का एक शेर है, 'बाज़ीचा-ए-अतफ़ाल है दुनिया मिरे आगे, होता है शब-ओ-रोज़ तमाशा मिरे आगे।', मैं वो पढ़ता था और मैं खुद से यही बोलता था कि अरे, इन लोगों को समझ नहीं है कि मैं कौन हूं। इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए खुद पर यह भरोसा जरूरी है।'

मुन्ना भैया ने मेरी टाइप कास्टिंग तोड़ी है

वेब सीरीज 'मिर्जापुर' का मुन्ना भैया हो या पिछली सीरीज 'ग्लोरी' का देव, दिव्येंदु डार्क किरदारों में ज्यादा नजर आते हैं। यह टाइप कास्टिंग है या उनकी चॉइस, यह पूछने पर वह कहते हैं, 'मुझे तो लगता है कि मुन्ना के बाद मुझे ज्यादा अलग-अलग किरदार ऑफर हुए। 'अग्नि', 'मडगांव एक्सप्रेस', 'लाइफ हिल गई' जैसे अलग-अलग काम मिले, तो मेरे लिए मुन्ना भैया ने टाइप कास्टिंग तोड़ी। वरना उससे पहले मैं कॉमेडी ही कर रहा था। जबकि, कॉमेडी मुझे ज्यादा मुश्किल लगती है। मेरी जो थिएटर में ट्रेनिंग रही है, फिल्म इंस्टीट्यूट में जो मेरी पढ़ाई रही है, मुझे ड्रामा, हैवी किरदार करना ज्यादा पसंद है।' हालांकि, दिव्येंदु यह भी कहते हैं कि उन्हें 'ग्लोरी' के देव का किरदार 'मिर्जापुर' के मुन्ना भैया से भी ज्यादा डार्क लगता है। वह कहते हैं, 'देव मेरी जिंदगी का सबसे डार्क किरदार है। मैंने उससे ज्यादा डार्क कभी कुछ नहीं निभाया।